● वर्ष-3
● अंक-30
रायपुर, बुधवार
13 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

# महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत, दर घटी

## अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 7.4 प्रतिशत से घटकर 6.83 प्रतिशत पर आई

**नईदिल्ली।** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.83 प्रतिशत हो गई। इसका बड़ा कारण यह है कि पिछले महीने की तुलना में सब्जियों की कीमतें कम हो गईं। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति जून के 4.87 प्रतिशत से बढ़कर 7.44 प्रतिशत हो गई थी। यह लगातार दूसरा महीना है जब सीपीआई मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सहनशीलता स्तर 2-6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक हो गई है। यह लगातार 47वां महीना है जब यह केंद्रीय बैंक के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर रहा है। एक आधार अंक एक प्रतिशत अंक का सौवां हिस्सा है।

अर्थशास्त्रियों ने शुरू में अगस्त के लिए खुदरा मुद्रास्फीति घटकर लगभग 7 प्रतिशत होने की भविष्यवाणी की थी, आधिकारिक डेटा और भी अधिक अनुकूल आंकड़ा दिखाता है। दिलचस्प बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में 6.59 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर थोड़ी अधिक 7.02 प्रतिशत रही। खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी का श्रेय आंशिक रूप से सब्जियों की कीमतों में गिरावट को दिया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवधि के दौरान अनाज, दालें, दूध और फलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है।अच्छी खबर यह है कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है और विशेषज्ञों को आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे गिरावट की उम्मीद है। भारत का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) जुलाई 2023 में 5.7 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू

वित्त वर्ष में यह सबसे ऊंची आईआईपी वृद्धि दर है। आईआईपी में वृद्धि व्यापक आधार वाली थी, जिसमें सभी तीन प्रमुख क्षेत्रों - विनिर्माण, खनन और बिजली - ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र में 6.3त्न, खनन क्षेत्र में 4.2त्न और बिजली क्षेत्र में 8.3त्न की वृद्धि हुई।

### कैसे इकट्ठा किए जाते हैं कीमतों के आंकड़े

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देशभर (सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) के उप-समूहों और समूहों के लिए भी जारी किए गए हैं। एनएसओ, एमओएसपीआई के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा साप्ताहिक रोस्टर पर व्यक्तिगत दौरे किए जाते हैं, जिसके माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चयनित 1114 शहरी बाजारों और 1181 गांवों से मूल्य आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अगस्त 2023 के महीने के दौरान एनएसओ ने 99.6 प्रतिशत गांवों और 98.3 प्रतिशत शहरी बाजारों से कीमतें इकट्ठा कीं। रिपोर्ट किए गए बाजारवार मूल्य ग्रामीण के लिए 88.8 प्रतिशत और शहरी के लिए 91.3 प्रतिशत थे।

## मोदी सरकार में बेलगाम महंगाई और मुनाफाखोरीः कांग्रेस

विपक्ष एक बार फिर महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) नेता हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जीवन बीमा सर्वेक्षण का जवाब दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इसके 43 प्रतिशत उपभोक्ता अब मौजूदा आर्थिक माहौल में मुद्रास्फीति को अपनी महत्वपूर्ण चिंता मानते हैं। विपक्ष एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के सर्वेक्षण परिणामों का हवाला दे रहा है जिसमें यह भी पता चला है कि पिछले पांच वर्षों के भीतर 47 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपनी पॉलिसियों को सरेंडर कर दिया था या नवीनीकृत नहीं किया था। कांग्रेस ने तो साफ तौर पर कहा है कि यह मोदी सरकार में बेलगाम महंगाई और मुनाफाखोरी का नतीजा है।

कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि पांच साल में 47प्रतिशत लोगों ने लौटाई जीवन बीमा पॉलिसी। ये मोदी सरकार में बेलगाम महंगाई और मुनाफाखोरी का नतीजा है कि लोग जीवन बीमा जैसी जरूरी सुविधा का खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं। इसके साथ ही उसने लिखा कि अच्छे दिन का सपना दिखाकर क्रूरू मोदी ने अपने ही देशवासियों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। आज महंगाई से हर मोर्चे पर लड़ रहे करोड़ों लोग एक आवाज में पूछ रहे हैं- मोदी जी, क्या यही है वो अमृतकाल? वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लूट की कोई नहीं सीमा, महँगाई ने छीना जीवन बीमा! उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मुनाफ़ाख़ोरी की नीति के चलते एक आम परिवार का घर चलाना मुश्किल हो चला है।

खड़गे ने आगे लिखा कि जानलेवा महँगाई का परिणाम यह है कि ज़रूरी जीवन बीमा भी लोग सरेंडर करने पर मजबूर हो गये हैं। पिछले 5 सालों में 47त्न लोगों ने जीवन बीमा पॉलिसी लौटा दी है। अगर ये है जनता की जेब का हाल, तो नहीं चाहिए ऐसा अमृत काल! जयराम रमेश ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई अनियंत्रित हो चुकी है। खाने पीने से लेकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ख़र्च में बढ़ोतरी से देशवासी परेशान हैं। दवाई से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ महंगा हो गया है। महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान आम और ग़रीब लोग हैं, क्योंकि उनकी आय नहीं बढ़ रही है।

## इन दिनों

✍ अमित शर्मा

## आर्थिक कॉरिडोर से गरीबों को क्या मिलेगा?

भारत ने जी20 का सफल आयोजन कर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी है। इंडिया, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जाने वाले रेल-समुद्री यातायात कॉरिडोर के निर्माण पर सदस्य देशों की सहमति को इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस कॉरिडोर के बनने से यूपी-बिहार या तमिलनाडु और केरल के सुदूर इलाकों में काम करने वाले किसानों-गरीबों को इससे क्या लाभ मिलेगा? एपीडा के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2022-23 में 13,185 करोड़ रुपये मूल्य की फल-सब्जियों का निर्यात किया था। इसमें 6219 करोड़ रुपये से ज्यादा के फल और 6965 करोड़ रुपये से अधिक की सब्जियां शामिल थीं। प्रोसेस्ड फूड और दालों को मिलाकर यह आंकड़ा 18 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा था। भारत आम, केला और पपीता जैसे फलों के उत्पादन में दुनिया में नंबर एक पर है, लेकिन इसके बाद भी हमारी फलों-सब्जियों के निर्यात में वैश्विक हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम है। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में फलों-सब्जियों को रखने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए अच्छी गुणवत्ता की और सस्ती दरों पर उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज चेनों की भारी कमी है। वैश्विक व्यापार के लिए यह कमी और ज्यादा हो जाती है। फलों-सब्जियों के देरी से बाजार में पहुंचने से व्यापारियों को भारी नुकसान होने की संभावना लगातार बनी रहती है। चूंकि, कहा जा रहा है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से यूरोपीय बाजारों में पहुंचने वाले फलों-सब्जियों के पहुंचने में 40 फीसदी का समय कम लगेगा, इससे भारतीय उत्पादों के यूरोपीय बाजार तक पहुंचने में इनके न खराब होने की दर बढ़ जाएगी। इसका सीधा लाभ भारतीय किसानों को मिलेगा। यूरोप भारत के कुल कारोबार का तीसरा सबसे बड़ा साझीदार है। वर्ष 2021 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.8 फीसदी व्यापार यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था। अमेरिका के 11.6 फीसदी और चीन के 11.4 फीसदी की व्यापारिक हिस्सेदारी होने के बाद भी यूरोप भारत के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका बड़ा कारण है कि भारत यूरोपीय देशों को कृषि उत्पादों, फलों-सब्जियों, कपड़ों और दवाओं का निर्यात करता है, जिसके कारण उसका निर्यात पक्ष यूरोप में बहुत संतुलित है, जबकि चीन से भारत ज्यादातर वस्तुएं आयात करता है और व्यापारिक असंतुलन बुरी तरह चीन के पक्ष में झुका हुआ है। भारतीय उत्पादकों से यूरोप के बाजारों तक पहुंचने में अलग-अलग देशों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अभी 30 से 45 दिन तक का समय लगता है। जबकि अनुमान है कि मुंबई से शुरू होने वाले 6000 किलोमीटर लंबे इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से यह समय 12 से 15 दिन तक कम हो जाएगा। समय के साथ खराब होने वाले कृषि, फल-सब्जी और डेयरी उत्पादों के संदर्भ में यह समय बहुत महत्त्वपूर्ण है।

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 49 करोड़ 50 लाख की लागत से 3.14 एकड़ में बनने वाले नए छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमिपूजन किया।

## 40प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज, शीर्ष पर केरल

**नईदिल्ली।** एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, संसद के 763 सदस्यों (सांसदों) में से 306 (40 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। यह डेटा सांसदों द्वारा अपना पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाला गया है। लगभग 194 (25 प्रतिशत) सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। स्व-शपथ हलफनामे में आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले सांसदों की सूची में केरल (7 प्रतिशत) शीर्ष पर है, इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र (57 प्रतिशत) और तेलंगाना

(50 प्रतिशत) का स्थान है।

बिहार (50 प्रतिशत) में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद तेलंगाना (9 प्रतिशत), केरल (10 प्रतिशत ), महाराष्ट्र (34 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (37 प्रतिशत) हैं। पार्टी-वार आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 385 सांसदों में से 139 (36 प्रतिशत), कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 (53त्न), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 36 में से 14 (39प्रतिशत), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के 6 में से 5 (83 प्रतिशत), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 8 में से 6 (75प्रतिशत) सांसद हैं। (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी (आप) के 11 सांसदों में से 13 (42 प्रतिशत), वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 13 (42 प्रतिशत) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के 8 सांसदों में से 3 (38 प्रतिशत) ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार, 32 सांसदों ने हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा 307) के मामलों की घोषणा की है। इक्कीस मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। उनमें से 4 सांसदों ने बलात्कार (आईपीसी धारा 376) से संबंधित मामलों की घोषणा की है। लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सांसद की औसत संपत्ति 38.33 करोड़ है। घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की औसत संपत्ति 50.03 करोड़ है जबकि बिना आपराधिक मामले वाले सांसदों की औसत संपत्ति 30.50 करोड़ है। तेलंगाना (24 सांसद) में 262.26 करोड़ की औसत संपत्ति के साथ सांसदों की उच्चतम औसत संपत्ति है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (36 सांसद) में 150.76 करोड़ की औसत संपत्ति के साथ और पंजाब (20 सांसद) में 88.94 करोड़ की औसत संपत्ति है।

**प्रमुख समाचार**

### चंद्रबाबू की नजरबंदी याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

**नईदिल्ली।** एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा हाउस रिमांड हासिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चंद्रबाबू नायडू को पिछले हफ्ते कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। विजयवाड़ा में

एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने मंगलवार को मामले में सीआईडी की दलील से सहमति जताई और चंद्रबाबू नायडू को हाउस रिमांड से इनकार कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश सीआईडी प्रमुख एन संजय ने कहा कि उन्हें कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने खतरे की आशंका का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को घर में हिरासत में रखने के लिए सोमवार को एक याचिका दायर की थी। रविवार को विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने चंद्रबाबू नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

### हरियाणा में आआपा ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान

**नईदिल्ली।** विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं लग रहा है। सभी पार्टियों ने इस बात का ऐलान किया है कि वे भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर सभी अपनी रणनीति को मजबूत

करने में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने हरियाणा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर मैदान में उतरेगी। आप के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी और वह किसी अन्य दल के साथ सीट शेयर नहीं करेगी। इतना ही नहीं, संदीप पाठक में यह भी कह दिया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हम सभी राज्यों में अपना संगठन बना रहे हैं। संदीप पाठक ने अपने वक्तव्य में यह भी बताया कि हरियाणा में सर्कल लेवल तक हमारा संगठन बन चुका है और आने वाले समय में गांव-गांव तक हमारी कमेटी बन जाएगी।

### नोटबंदी के दौरान आरबीआई पर आरोप, याचिका खारिज

**मुंबई।** शहर के एक कार्यकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए, जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान लाभार्थियों को बेहिसाब मुद्रा का आदान-प्रदान करने में गलत गतिविधियों में शामिल था, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई आपराधिक मामला तय नहीं किया जा सकता है। आरबीआई पर भी जांच हो सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता किसी भी अपराध के घटित होने का खुलासा करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय ने 8 सितंबर को फैसला सुनाया, जिसकी एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। इसमें कहा गया है कि आरबीआई हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अदालतों को मौद्रिक नियामक ढांचे में तब तक जाने से बचना चाहिए जब तक कि अदालत की संतुष्टि के लिए यह न दिखाया जाए कि एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अजय एस 2016 में जब केंद्र सरकार ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) की मदद से नोटबंदी की थी, तब 500 और 1,000 रुपये के नोट बदले गए थे।

### फिर से फैल रहा है निपाह वायरस! केरल में 2 की मौत

**कोझिकोड ।** केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य का इलाज चल रहा है। जिन चार लोगों का इलाज चल रहा है, वे पीड़ितों में से एक के करीबी रिश्तेदार हैं। इससे पहले दो

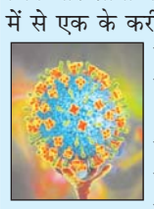

मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया था। मृत व्यक्तियों और निपाह वायरस संक्रमण के समान लक्षणों वाले उपचाराधीन लोगों के नमूने अंतिम परीक्षण और पुष्टि के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए थे। स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक के लिए मंगलवार सुबह कोझिकोड पहुंची स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मीडिया को बताया था कि नमूनों के प्रयोगशाला परिणाम शाम तक उपलब्ध होंगे। बुखार के कारण मरने वाले दो मृत व्यक्तियों के संपर्कों की पहचान कर ली गई है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। उच्च जोखिम श्रेणी के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, यदि निपाह की पुष्टि हो जाती है, तो उन क्षेत्रों में सामाजिक समारोहों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा।

### पांडवों का लाक्षागृह या मजार मामला सिविल कोर्ट में

**नईदिल्ली।** आप काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जानते होंगे। आपने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बागपत में भी एक ऐसी जगह है जिसपर धर्म युद्ध छिड़ा है।

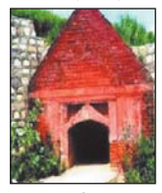

लाक्षागृह और मजार को लेकर चल रहे विवाद पर 53 साल बाद अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन जजमेंट अगली तारीख के लिए टल गई है। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों के हड़ताल पर होने की वजह से सिविल कोर्ट ने जजमेंट नहीं सुनाया। अगली तारीख में जजमेंट आएगा। जिसके बाद ये साफ होगा कि विवादित स्थल पर किसका हक है। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर बागपत के बरनावा में 108 बीघा जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। जिस जगह पर विवाद है उसे हिंदू पक्ष पांडवों का लाक्षागृह बताते हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये उनका कब्रिस्तान है। पूरा विवाद साल 1970 में शुरू हुआ था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकीम खान ने लाक्षागृह टीले को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताते हुए मुकदमा दाखिल किया था।

## चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सनातन धर्म पर हमले तेज होते जा रहे

**नीरज कुमार दुबे**

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल सनातन धर्म पर हमला तेज करते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण घटक और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रमुक के नेता उदयनिधि स्टालिन और सांसद ए. राजा के बाद अब द्रमुक नेता के. पोनमुडी ने सनातन धर्म पर हमला कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे भी उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म विरोधी बयान का एक तरह से समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा, बिहार में सत्तारुढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से भी हिंदू आस्था को चोट पहुँचाने वाली टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य तो सनातन धर्म के विरोध में ताल ठोक कर खड़े हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एक तरह से राम के काम में अड़ंगा लगाने वाला काम करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देशभर से कई हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वे गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। इन सब बयानों पर आप गौर करेंगे तो एक चीज साफ नजर आयेगी कि विपक्षी गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक के बाद ही सनातन धर्म विरोधी बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या

वाकई यह आरोप सही हैं कि उस बैठक में सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था को ठेस पहुँचाने की रणनीति बनाई गयी होगी? यहां यह सवाल भी उठता है कि अब जब विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है तब क्या इस अभियान को आगे बढ़ाने की रूपरेखा बनेगी या इस अभियान के तहत अब तक कितनी कामयाबी हासिल होगी इसकी समीक्षा की जायेगी?

### भाजपा का आरोप

हम आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से लगातार आ रहे सनातन धर्म विरोधी बयानों को देखते हुए भाजपा ने तो आरोप लगा भी दिया है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म पर हमला विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) का गुप्त एजेंडा है। पार्टी ने इस प्राचीन धर्म के बारे में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेताओं की लगातार आलोचनात्मक टिप्पणियों के बीच विपक्षी नेताओं की 'चुप्पी' पर भी सवाल उठाए। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी इस मामले पर अगर चुप्पी साधे रहेंगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सनातन धर्म का विरोध करना 'इंडिया' के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। रविशंकर प्रसाद ने द्रमुक के एक नेता की उस हालिया टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का विरोध करना संगठन का एजेंडा है। इस बारे में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तमिलनाडु के नेता ने जो कहा है वह विपक्षी गठबंधन के बारे में सही ही है।

''भाजपा इस गठबंधन से एक स्पष्ट प्रस्ताव लाने का आग्रह करेगी कि वह इससे खुद को (द्रमुक की आलोचना से) पूरी तरह अलग करता है और यह उनका एजेंडा नहीं है।'' द्रमुक द्वारा अपनी आलोचना को सही ठहराने के लिए सनातन धर्म को हिंदुओं के बीच जातिगत भेदभाव की प्रथा से जोड़ने पर भाजपा नेता ने कहा कि शबीर, केवट और संत रविदास जैसे पिछड़ी जातियों के श्रद्धेय लोगों को समर्पित मंदिर बनाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति और समुदाय की पृष्ठभूमि के बावजूद अपनी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकता है।कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रसाद ने कहा कि द्रमुक से लेकर राजद और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसे दलों के कुछ विपक्षी नेता सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े पवित्र ग्रंथों की आलोचना करने में मुखर रहे हैं, लेकिन क्या वे अन्य धर्मों और उनके पवित्र व्यक्तित्वों की आलोचना करने का साहस जुटा सकते हैं? उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत का हर रोज अपमान किया जा रहा है।

# कांग्रेस विधायक के खिलाफ पोल खोल धरना प्रदर्शन, भाजपा ने की सत्ता से बाहर करने की अपील

**मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर।** बीजेपी ने मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया।बीजेपी की माने तो विधायक विनय जायसवाल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। पार्टी पदाधिकारियों की माने तो विधायक क्षेत्र में कई तरह के अवैध कामों को शह दे रहे हैं।इसलिए बीजेपी ने पोल खोल धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखी है। मनेंद्रगढ़ के गांधी चौक में हुए इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विधायक विनय जायसवाल समेत कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला।श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मनेंद्रगढ़ विधायक की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार से पूरा क्षेत्र परेशान है।पिछले चुनाव से पहले कुछ सफेद पोश लोग जेल गए, कुछ बेल पर हैं। ऐसे लोगों ने बीजेपी से जुड़े लोगों की राजनीतिक चरित्र की हत्या करने की कोशिश की थी।फर्जी सीडी बनाकर बदनाम करने का काम किया था।वैसा ही गंदा खेल डॉक्टर विनय जायसवाल इस क्षेत्र में खेल रहे हैं रहे हैं।

श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा साथियों ऐसे भ्रष्ट विधायक को, ऐसे क्षेत्र का विनाश करने वाले विधायक को, ऐसे अवैध शराब के दुकान चलाने वाले विधायक को उखाड़ फेकेंगे। एक स्वच्छ विधानसभा का निर्माण करने के लिए हम सब आज संकल्प लें कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधायक की कुर्सी पर बैठाएंगे।

**कांग्रेस विधायक पर निष्क्रिय रहने का लगाया आरोप** - वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी ने कहा कि मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल की कारगुजारियों, भ्रष्टाचार और पांच साल तक इनकी निष्क्रियता को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा हमने क्रमिक रूप से प्रदर्शन खड़गवां में भी किया, चिरमिरी में भी किया। भ्रष्टाचार की बारात निकाली। खड़गवां में सड़क जाम के बाद तालाबंदी की। आज मनेंद्रगढ़ में किया है। आगामी दिनों में भी इसी तरह से कांग्रेस विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनेंद्रगढ़ विधायक ने एक ऑडियो क्लिप जारी करके पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसमें विधायक ने दावा किया था कि पूर्व विधायक क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े हैं। साथ ही साथ कई आदिवासियों की जमीन अपने नाम करवा ली है। वहीं इन आरोपों पर श्याम बिहारी जायसवाल ने भी पलटवार करके विधायक को घेरा था। इसी कड़ी में एक बार फिर बीजेपी ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला है।

# कोरबा में हाथियों के झुंड ने बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला

**कोरबा।** जिले में हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है. जंगली हाथियों के झुंड ने एक 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। पसान वन क्षेत्र के अंतर्गत पंगावा ग्राम पंचायत में सोन कुंवर पर हाथियों ने उस समय हमला किया, जब वह अपने घर के अंदर सो रही थी। लगभग 42 हाथियों का एक झुंड दिन के तड़के गांव के करीब पहाड़ी पर बसी बस्ती बैगापारा में भटक गया। इनमें से कुछ हाथी पीड़ित के घर में घुस गए और एक कमरे में रखे बाजरे को खाने लगे। परिवार के अन्य सदस्य घर से भागने में सफल रहे, लेकिन उसी कमरे में सो रही कुंवर की कुचलकर मौत हो गई।

कोरबा में हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है। रविवार को कटघोरा वनमंडल के ही चोटिया कोयला खदान के डंपिंग एरिया में हाथी के हमले में दो महिलाओं की मौत हो गई और एक पुरुष घायल हो गया। कटघोरा वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) कुमार निशांत ने कहा कि पसान वन क्षेत्र मृतक के परिजनों को 25,000 रुपये की राहत राशि दी गई है, जबकि बाकी मुआवजा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दी जाएगी। हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए वन कर्मियों को तैनात किया गया है।

डीएफओ कुमार निशांत ने कहा हाथियों का झुंड पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है और ग्रामीणों को इसके बारे में सतर्क कर दिया गया है। 42 हाथियों में से 35 आज सुबह पंगावा से पाली ग्राम पंचायत की ओर चले गए, जबकि सात अलग हो गए और घटना के बाद कोरबी वन क्षेत्र की ओर चले गए।

### छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष

छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मानव हाथी संघर्ष, पिछले एक दशक से चिंता का कारण रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह खतरा धीरे धीरे मध्य क्षेत्र के कुछ जिलों में फैल गया है। सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, बलरामपुर और कांकेर जिले इस खतरे का सामना कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक पिछले तीन सालों में राज्य में हाथियों के हमलों में 230 से ज्यादा लोग मारे गए।

# छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज रेल रोको आंदोलन

■ आरपीएफ ने किए सुरक्षा के इंतजाम

**बिलासपुर।** केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को खत्म करने की साजिश रच रही है। यह आरोप छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि केंद्र सरकार रेलवे को निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रच रही है और बिना किसी ठोस वजह के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर रही है। इससे रोजाना छत्तीसगढ़ के लाखों यात्रियों को परेशानी हो रही है। इन आरोपों के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेशभर में रेल रोको आंदोलन करने की योजना बनाई है।

13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में एक साथ ट्रेनों को रोका जाएगा। जिला सहित ब्लॉक मुख्यालय और छोटे छोटे स्टेशन में भी कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेनों को रोकेंगे। कांग्रेस इस रेल रोको के जरिए बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी में हैं।

### पीसीसी ने रेलवे पर लगाए ये आरोप

देश भर के 6800 रेल स्टॉपेज बंद कर दिए गए, जिसमें से 200 छत्तीसगढ़ में हैं। साधारण पैसेंजर मेमू डेमू ट्रेन को स्पेशल बनाकर दोगुना किराया वसूला जा रहा है। स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बों की संख्या भी घटाई गई है।

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, विजय केशरवानी ने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जोन देश को सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला जोन है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान छत्तीसगढ़ की

जनता हो रही है। कोरोना काल के समय जिन ट्रेनों को बंद किया गया उन्हें दोबारा चालू नहीं किया गया। कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया।भाजपा जानती है कि छत्तीसगढ़ में उनकी जमीन खिसक गई है इस वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान किया जा रहा है।

ब्लॉक अध्यक्ष, जावेद मेमन ने कहा जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है जब से ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। यात्री ट्रेनों को रोककर सिर्फ माल गाड़ियों को चलाया जा रहा है। रेल रोको आंदोलन के जरिए कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को जवाब देगी। ट्रेनें शुरू नहीं करने पर उग्र आंदोलन करेंगे।

### पिछले साढ़े तीन साल में 67382 ट्रेनों को किया रद्द

साल 2020 में 32757 ट्रेनें निरस्त
साल 2021 में 32151 ट्रेनें निरस्त
साल 2022 में 2474 ट्रेनें निरस्त
साल 2023 में (अप्रैल माह तक) 208 ट्रेनें निरस्त।
अगस्त 2023 में 24 ट्रेनें रद्द।

छत्तीसगढ़ से जाने वाली नौतनवा और सारनाथ एक्सप्रेस 64 दिन तक रद्द कर दी गयी। जिसके कारण दो महीने तक लोग अस्थि कलश गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए।

### ट्रेन कैंसिल होने पर रेलवे की सफाई

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने कहा कि कोरोनाकाल के दौरान बंद की गई सभी ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक विभिन्न स्टेशनों में अलग-अलग ट्रेनों के 53 ठहराव दिए गए हैं। यात्रियों को कंफर्म बर्थ दिलाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से इस साल के अप्रैल माह तक अलग अलग ट्रेनों में 78 स्थायी कोच लगाए गए हैं। इसके अलावा त्योहार और छुट्टियों में 25 से 50 अस्थायी अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं। अप्रैल से सितंबर तक रेल विकास कार्यों में चलने वाली औसत यात्री गाड़ियों में एक प्रतिशत से भी कम को ही कैंसिल किया गया है।

# छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक से पारंपरिक खेलों को मिली नई पहचान: संसदीय सचिव

■ पारंपरिक खेलों में लगभग 1800 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर

**बिलासपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और सभी आयु वर्ग के लोगों को मंच प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेलों की शुरूआत की गयी है। ग्राम और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं पूरी होने के बाद आज जिला स्तरीय ओलम्पिक खेलों की शानदार शुरूआत संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह के मुख्य आतिथ्य में स्व.बी.आर यादव बहतराई स्टेडियम में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्री रामशरण यादव ने की। यह खेल 12 से 13 सितंबर 2023 तक चलेगा। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल में 18 वर्ष आयुवर्ग के बालक-बालिका, 18 से 40 और 40 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के महिला-पुरुष खिलाड़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।

जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़िया संस्कृति को सहेजने का काम किया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक

विरासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। इस आयोजन से पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिली है। इन खेलो में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने उन्मुक्त होकर खेला है। उन्होंने कहा कि अब तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने खिलाड़ियों से आव्हान किया कि वे खेल को खेल भावना से खेलें। महापौर श्री रामशरण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो रहे पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है। उनके द्वारा राज्य में सभी वर्ग की बेहतरी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आज पहले दिन सभी प्रतियोगिताएं पुरूष वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। कल दूसरे दिन 13 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चार विकासखंड और दो नगरीय क्लस्टर के 850 महिला और 922 पुरूष इस प्रकार कुल 1722 प्रतिभागी खेलों में अपना हुनर दिखाएंगे। इस अवसर पर नगर निगम सभापति श्री शेख नजरूदीन, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक, योग आयोग के सदस्य श्री रविन्द्र सिंह, अरपा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभयनारायण राय, बिलासपुर मंडी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री अजय अग्रवाल, विभागीय अधिकारी, बड़ी संख्या खिलाड़ी, शहरी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

## छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

### सरपंच को जानकारी दिए बिना सचिव ने निकाल ली राशि

**बेमेतरा।** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा ने वित्तीय अनियमितता किए जाने व अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण पंचायत सचिव अकोली (तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत आनंदगांव) जनपद पंचायत बेरला अमित कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत बेरला निर्धारित किया गया है। सस्पेंड अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में जनपद पंचायत बेरला के जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए कहा गया है कि आनंदगांव के सरपंच की बिना जानकारी के राशि का अवैध रूप से आहरण-भुगतान किया गया। इस मामले को लेकर शिकायत हुई थी, जिसके बाद जांच की गई थी।

### बारिश और ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई किसानों की फसल

**बेमेतरा।** छत्तीसगढ़ में कृषि प्रधान जिले के नाम से प्रसिद्ध बेमेतरा में किसानों को बीते छह माह से फसल बीमा राशि नहीं मिली है। इन किसानों ने बीते रबी सीजन में बारिश व ओलावृष्टि को देखते हुए अपने चना की फसल का बीमा कराया था। बीते सीजन में जिले में बारिश व ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की फसल तबाह हो गई थी। इसके बाद इन्हें मुआवजा मिलता, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली है। इन्हीं समस्या को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कलेक्टर जनचौपान में किसानों ने अपनी समस्या रखी। ग्राम कन्हेरा से पहुंचे किसानों ने बताया कि उन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया था। उन्हें उम्मीद थी कि राशि मिल जाएगी, लेकिन छह माह बाद भी राशि नहीं मिली। इसी प्रकार जनचौपाल में बेरला तहसील के ग्राम करेली निवासी परदेशी राम देवांगन ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किस्त की राशि प्रदान करने, ग्राम सोमई खुर्द निवासी उत्तरा साहू ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने के संबंध में आवेदन दिया।

### रजनीकांत की अग्रिम याचिका पर सुनवाई से जज का इंकार

**बिलासपुर।** कोयला घोटाले मामले में सलाखों के पीछे बंद रजनीकांत तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की की बेंच ने सुनवाई करने से आज मना कर दिया। माननीय जज द्वारा सुनवाई से इंकार किए जाने के बाद अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से दूसरे बेंच को स्थानांतरित किया जाएगा। उल्लेखनीय हैं कि कोयला घोटाले के एक प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी को 2100 करोड़ रुपये के कोल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आरोपी बनाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो जस्टिस पांडेय की बेंच में सुनवाई के लिए रखा गया था। जस्टिस पांडेय ने इसे सुनने से इंकार कर दिया। इसके पहले इसी प्रकरण में जस्टिस पांडेय सुनील कुमार अग्रवाल व सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की सुनवाई करने से भी इंकार कर चुके हैं।

### बिलासपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 17 लाख कैश जब्त किया

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ के इन दिनों भारी मात्रा में कैश मिलने का सिलसिला चल रहा है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला और राज्यों की सीमा पर चैकपोस्ट बनाकर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इस पर अमल करते हुए लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग में लाखों रुपये कैश जब्त किया जा रहा है। सोमवार को बिलासपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान 17 लाख रुपये कैश मिला। तारबाहर थाना पुलिस व्यापार विहार चौक में गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी। जांच के दौरान महाराणा प्रताप चौक की तरफ से आ रही क्रेटा कार को रुकवाकर जांच करने पर कार के अंदर एक काले रंग का बैग मिला। बैग में ढेर सारे रुपये रखे हुए थे। पुलिस ने कार चालक से रुपयों के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाया। जिसके बाद पुलिस ने रुपये जब्त कर लिए। थाना प्रभारी मनोज नायक ने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में जांच जारी है।

### गृहमंत्री की सभा में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप हुई दुर्घटनाग्रस्त

**जगदलपुर।** दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण में मंगलवार की सुबह केंद्रीय गृह मंत्री की सभा में शामिल होने जा रहे है ग्रामीणों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 10 ग्रामीण घायल हो गए, घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ही आमजनों ने घायलों को बेहतर उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका उपचार जारी है। बता दें कि मंगलवार को दंतेवाड़ा से गृहमंत्री अमित शाह भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे। अमित शाह की सभा में शामिल होने दंतेवाड़ा जिले के अलावा सुकमा, बीजापुर से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण पिकअप और दूसरे वाहनों से जा रहे थे। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री की सभा में शामिल होने आ रहे कटेकल्याण के भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी पिकअप मेटापाल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में लगभग लोग घायल हो गए।

# धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राठिया और कंवर समाज का दबदबा

**धरमजयगढ़।** छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में कुल 24 विधानसभा सीटें है। इनमें से एक सीट है धरमजयगढ़ विधानसभा सीट। धरमजयगढ़ रायगढ़ जिले में पड़ता है। ये सीट एसटी के लिए रिजर्व है। ये पूरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। लालजीत सिंह राठिया इस क्षेत्र से विधायक हैं। यहां से बीजेपी ने हरिश्चंद्र राठिया को प्रत्याशी घोषित किया है।

**जातिगत समीकरण**- ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। एसटी के लिए रिजर्व इस सीट पर राठिया और कंवर समाज के लोग लगभग 65 हजार हैं। ईसाई 30 हजार, मंजवार, बैगा 15-17 हजार, अग्रवाल 2 हजार, अगरिया, तेली, साहू12 हजार और बंगाली 20 हजार हैं। हरिश्चंद्र राठिया एसटी वर्ग से आते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार हरिश्चंद्र राठिया पर भरोसा जताया है। हरिश्चंद्र राठिया पिछले ढाई दशक से बीजेपी में सक्रिय हैं। बीजेपी के विभिन्न संगठन के पदों पर रहकर बेहतर सेवाएं भी दे चुके हैं।हरिश्चंद्र राठिया दो बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं।

**वर्तमान विधायक**- धरमजयगढ़ विधानसभा से विधायक लालजीत सिंह राठिया रायगढ़ के कद्दावर नेता है। लालजीत सिंह पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया के बेटे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी लीनव बिरजु राठिया को 40335 वोटों से हराया था।

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 207690 है। यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 101873 है। वहीं, महिला मतदाताओं की संख्या 105813 है। इस सीट पर 4 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।

**मुद्दा और समस्याएं**- धरमजयगढ़ विधानसभा सीट में लगभग 80 फीसद क्षेत्र जंगल है। इस क्षेत्र में चिनार, साल, सागौन, शीशम जैसी कीमती इमारती लकड़ियां पाई जाती है। यहां के आदिवासी महुआ, फल, बीड़ी पत्ता, चिरौंजी, जामुन को जमा करके बेचते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिलता है। हालांकि यहां वन्यजीवों का खतरा बना रहता है। इस क्षेत्र में हाथियों का आना-जाना लगातार बना रहता है। क्षेत्र में हाथियों से अब तक दर्जनों लोगों की जान ले ली है। साथ ही फसलों को भी खूब नुकसान पहुंचाया है। इस क्षेत्र में वन्यजीवों से लोगो की जान को खतरा बड़ी समस्या है।

**2018 चुनाव के नतीजे**- साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया ने 79276 वोटों से जीत हासिल की थी। लालजीत सिंह ने भाजपा के ओमप्रकाश राठिया को हराया था। इस चुनाव में बीजेपी को 59288 वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 50.07 फीसद वोट मिले थे। वहीं, बीजेपी को 37.45 फीसद वोट मिले थे।

**विनिंग फैक्टर**- इस क्षेत्र में एसटी के लिए रिजर्व है। यही कारण है कि यहां से पार्टी भी एसटी वर्ग के प्रत्याशियों को ही चुनते हैं। इस क्षेत्र में राठिया समाज के प्रत्याशियों को ही पार्टी उतारती है। क्षेत्र में 65 हजार से अधिक राठिया और कंवर समाज के लोग रहते हैं। यही समाज इस क्षेत्र में विनिंग फैक्टर हैं। इस समाज के लोग ही यहां चुनाव में निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं।

# जनगणना में रखा जाए आदिवासी धर्म कोड आदिवासी समाज ने रैली निकलाकर किया हंगामा

**कबीरधाम।** सहसपुर लोहारा में आदिवासी समाज के लोग सोमवार को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई ने समाज की क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े 15 सूत्रीय मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्राम सूरजपुरा से रैली निकालकर सहसपुर लोहारा बस स्टैंड में सभा का आयोजन किया गया।

सैकड़ों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग पैदल चलते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां सड़क पर बैठकर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। सर्व आदिवासी समाज संयुक्त सचिव कामू बैगा ने बताया कि देश में होने वाले जनगणना के कॉलम में अब तक धर्म कोड में आदिवासी धर्म का ऑप्शन नहीं रहता था। जबकि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए।

सहसपुर लोहारा ब्लॉक के जिन गांव मे 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या में आदिवासी निवास करते हैं, इसे आदिवासी ग्राम घोषित किया जाए।

जिले में अभी भी समाज के कई लोगों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास पुराने दस्तावेज की कमी है। ऐसी स्तिथि में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके अलावा आदिवासी समाज के पुरुष या महिला गैर आदिवासी से विवाह करते हैं, तो उन्हें आदिवासी के आधार पर मिलने वाली सुविधा से वंचित रखा जाए, साथ ही उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए।

# मैं भाषण देने नहीं सवाल पूछने आया हूं : डॉ. रमन

**दंतेवाड़ा।** पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा शुरु होने से पूर्व आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं दंतेवाड़ा में भाषण देने नहीं आया है बल्कि यहां के निवासियों से सवाल करने आया हूं कि पूर्ववर्तीय भाजपा सरकार ने बस्तर अंचल के विकास के लिए जो कार्य किए थे वे पिछले पांच वर्षों में कहीं पर दिखाई नहीं दिए, केवल चारों ओर भ्रष्टाचार ही दिखाई दिया। लोगों को योजनाओं के नाम पर ठगा जा रहा है। जो योजनाएं उनकी सरकार ने आदिवासी और नागरिकों के हित में शुरु की थी उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया। मुझे विधानसभा चुनाव में इन सवालों का जवाब आप बहुत अच्छे ढंग से देंगे।

डा. रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने पूरे विश्व में भारत करवट बदल रहा है। उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार को निकम्मा करार देते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार ही बढ़े हैं। विकास के नाम पर

प्रगति राज्य में कहीं दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई देता है तो केवल भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि माता का आर्शीवाद मिला और आपका आर्शीवाद मिला तो यह परिवर्तन होकर रहेगा। वर्तमान सरकार ने कोयला से लेकर रेत तक घोटाला किया है। आपके आर्शीवाद से मैं तीन बार मुख्यमंत्री बना, बस्तर के विकास की कल्पना को स्वीकार करने संकल्प लिया और बस्तर की सबसे बड़ी समस्या नमक की थी जिसे हमारी सरकार ने निःशुल्क जनता को दी। नमक छोटा मुद्दा नहीं है यह बस्तर के स्वाईपान से जुड़ा हुआ है। आपके आर्शीवाद से बस्तर के आदिवासी कोदो, कुटकी से अपना जीवन यापन करते थे, पालनयन होता था। हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और 1 रुपये किलो चांवल की शुरुआत राज्य में की। सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि पलायन पर प्रतिबंध लग गया क्योंकि हमने लोगों को यहीं पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। डा. रमन सिंह ने जनता से पूछा कि दंतेश्वरी माता परिसर का सौंदर्यीकरण कब हुआ और किसने किया? जब भाजपा की सरकार बनी और मध्यप्रदेश से अलग होने के बाद 20 प्रतिशत आरक्षण को 32 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय भी भाजपा का था।

### ओम माथुर ने दिखाई परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी

भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के रथ को उत्तराखंड-उत्तरप्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडेय, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा के प्रत्याशी और अनेक गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। विशाल मोटर साइकिल में लोग शामिल हुए।

## कांग्रेस के 9 सवाल के जवाब में भाजपा ने दागे 16 सवाल

**रायपुर।** कांग्रेस के 9 सवाल के जवाब में भाजपा ने 16 सवाल दागे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि परिवर्तन यात्रा शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के हाथ पैर फूल गए हैं। कांग्रेस की सांसें उखड़ गई हैं। जिस कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता को अपने 5 साल का हिसाब किताब देना चाहिए। जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, वह परिवर्तन यात्रा के अवसर पर भाजपा से कुतर्क पूर्ण सवाल पूछ रही है। कांग्रेस को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

### बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे 16 सवाल

पहला सवाल कांग्रेस सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे कि झीरम के हत्यारे नक्सलियों को राहुल गांधी ने क्लीनचिट क्यों दी थी? क्या कोई गुप्त समझौता है? दूसरा सवाल यह है कि भूपेश बघेल झीरम का सबूत जेब में क्यों रखे हैं, क्या राहुल के आदेश पर वह सबूत जब में ही हैं या नक्सलियों से सौदा है? तीसरा सवाल यह है कि सबूत छुपाने का अपराध क्यों किया गया और सबूत छुपाने के अपराधी को क्या दंड मिलना चाहिए? चौथा सवाल यह है कि 5 साल तक छत्तीसगढ़ और 50 साल तक देश की सत्ता में रहने के बावजूद बस्तर को दुनिया का सबसे बीमारू इलाका बनाने के लिए कांग्रेस माफी क्यों नहीं मांगती? पांचवा सवाल यह है कि इलाज के अभाव में छत्तीसगढ़ के 39000 बच्चों की मौत हुई% जिनमें अधिकांश बच्चे बस्तर सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्र के हैं! भूपेश बघेल और कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? छठवां सवाल यह है कि कांग्रेस का हाथ तेंदूपत्ता दलालों के साथ क्यों है? आदिवासियों को तेंदूपत्ता बोनस क्यों नहीं दिया गया? सातवां सवाल यह कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग का मकसद क्या है? टारगेट किलिंग करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आठवां सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में एक लाख से अधिक महिलाएं गायब हो गई हैं। कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध रखी है? नौंवा सवाल यह कि आदिवासी बच्चियों के दैहिक शोषण की घटनाएं हो रही हैं। इनमें कांग्रेस के लोग संलिप्त पाए जाते हैं लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दसवां सवाल यह है कि अटल जी ने आदिवासी उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ निर्माण का विरोध क्यों कर रहे थे? ग्यारहवां सवाल यह कि आदिवासी शोषण की जिम्मेदार कांग्रेस आदिवासियों से माफी क्यों नहीं मांगती? बारहवां सवाल बस्तर महाराज प्रवीरचंद्र भंजदेव को गोलियों से भूनने वाली कांग्रेस ने माफी क्यों नहीं मांगी? तेरहवां सवाल यह है कि आदिवासी आरक्षण को निरस्त कराने वालों को कांग्रेस ने पुरस्कृत क्यों किया है? 14वां सवाल यह कि बस्तर में जिला केडर की भर्तियां बंद कर आदिवासियों को रोजगार से वंचित क्यों किया गया? 15वां सवाल यह है कि कांग्रेस नक्सलियों की प्रवक्ता बनकर सामने क्यों आती है? 16वां सवाल यह कि पिछले विधानसभा चुनाव में मिले आदिवासियों के समर्थन के बावजूद बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की अस्मिता पर आघात क्यों पहुंचाया

## संक्षिप्त समाचार

### मुख्यमंत्री से बस्तर माहरा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके

निवास कार्यालय में बस्तर संभाग से आए माहरा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री का माहरा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मात्रात्मक त्रुटि में सुधार कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री बघेल से प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्षों से मात्रात्मक त्रुटि सुधार की लंबित मांग पूरी होने से पूरे समाज में हर्ष है। अब समाज के सभी लोगों खासकर युवाओं को जाति प्रमाणपत्र बनने से आगे बढने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, माहरा समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष श्री सामू कश्यप, श्री श्रीराम नाग, श्री नवल नाग, श्री गणेश कावड़े, श्री सुंदर सोढ़ी, श्री चन्द्र बघेल, श्री पवन कश्यप, श्री तुलाराम कश्यप सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

### सौरभ निर्वाणी को कारण बताओ नोटिस

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बेमेतरा के इंका नेता सौरभ निर्वाणी को स्थानीय/क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ अनर्गल नारेबाजी कर पार्टी संगठन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है जो पार्टी संगठन के अनुशासन के खिलाफ है। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको कारण बताओं नोटिस जारी किया है। उनसे कहा गया है कि जारी नोटिस का लिखित जवाब/स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजे।

### राज्य के 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र मॉडल केन्द्र के रूप में हो रहे विकसित

**रायपुर।** बच्चों तथा महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं में मैदानी स्तर पर सुचारू रूप से संचालन के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों का सक्षम होना जरूरी है। इसे देखते हुए राज्य के 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें से 1047 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आकर्षक रूप देकर बाल सुलभ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों एवं 20 विकासखण्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए स्वयं का आंगनबाड़ी भवन होना आवश्यक है। जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन नहीं हैं, वहां हितग्राहियों की सुविधा के लिए राज्य शासन द्वारा अधिकाधिक संख्या में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

### अग्रसेन जयंती के लिए अग्रवाल सभा ने बनाई 12 समितियां

**रायपुर।** अग्रवाल सभा ने अग्रसेन जयंती के लिए 12 समितियों का गठन किया है। इसी सिलसिले में सभा के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने सभी समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के नामों की घोषणा की। 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी। हालांकि 21 दिवसीय समारोह की शुरुआत 24 सितंबर को मोहल्ला समितियों के कार्यक्रमों से होगी। अग्रवाल सभा जयंती प्रचार प्रसार प्रभारी योगेश अग्रवाल और प्रमोद जैन ने बताया कि आयोजन के लिए बनाई गई समन्वय समिति में जगदीश प्रसाद अग्रवाल, नवलकिशोर अग्रवाल, हनुमान प्रसाद अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल, कैलाश मुरारका व रतनलाल गोयल शामिल हैं। मनीष अग्रवाल को जयंती प्रभारी जबकि आनंद गोयल को शोभायात्रा प्रभारी बनाया गया है।

## नवा रायपुर के कमर्शियल हब में 540 वर्गफीट में मिलेगा व्यवसायियों को भूखण्ड: मुख्यमंत्री

■ राज्य में उद्योगों को मिल रहा है एक बेहतर वातावरण

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर अटलनगर के सेक्टर-35 में आयोजित समारोह में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं कमर्शियल हब, एरोसिटी और शहीद स्मारक का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि देश के सबसे बड़े थोक व्यवसायिक बाजार का शिलान्यास आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हो रहा है जिससे राज्य के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले भविष्य को देखते हुए ये भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकर्पण किए जा रहे हैं. राज्य के लोगों की हमसे अपेक्षाएं थीं जिसे साकार करने के लिए हमने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है।

श्री बघेल ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को आगे बढने के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर सके और हमने राज्य के किसानों के लिए ऐसा ही वातावरण तैयार किया है. इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में सुधार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति व पर्यटन को बढ़ावा देने का वातावरण भी हमने तैयार किया है। श्री बघेल ने कहा कि हम उद्योग को भी एक वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए मैने व्यवसायियों से कहा था कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को सबसे बेहतर बनाना है और इस प्रयास से प्रदेश में उद्योगों की संख्या बढ़ी है व लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों की मांग पर एक बड़ी घोषणा करते हुए नवा रायपुर के कमर्शियल हब में 540 रूपए वर्गफीट में व्यवसायियों को भूखण्ड आवंटित करने की बात कही. उन्होने कहा कि इसकी वजह से कमर्शियल हब के निर्माण में लगने वाली अतिरिक्त राशि की वहन राज्य सरकार करेगी।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत विविध कार्यों के इस शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आम लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है. उन्होने कहा कि सरकार की ये प्राथमिकता है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो ताकि छत्तीसगढ़ का लगातार विकास होता रहे।

नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर-23, 24, 34, 35 और 40 में 1083 एकड़ में कमर्शियल हब विकसित किया जा रहा है। इसी तरह नवा रायपुर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं रमचण्डी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में एरोसिटी विकसित की जा रही है। शहीद स्मारक की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में व्हीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जा रही है। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, विधायक श्री धनेन्द्र साहू, मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार डॉ. राकेश गुप्ता तथा छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स अध्यक्ष अमर परवानी के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

## मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का किया लोकार्पण

### सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से होगा नया मंडी बोर्ड भवन

**रायपुर।** मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने इस भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 40 करोड़ रूपए की लागत से तैयार किए गए इस भवन में बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा। लगभग 1 लाख 58 हजार वर्गफीट में बनाए गए इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों संचालित होंगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा के लिए राज्य में मंडी का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जानी है। इसको देखते हुए धान संग्रहण केन्द्रों को भी मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मिलेट्स की खेती को भी लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी की जा रही है। राज्य में किसान हितैषी नीतियों के फलस्वरूप बस्तर अंचल में खेती-किसानी के प्रति रूझान बढ़ा है। पहले बस्तर में सब्जी का उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा था अब बस्तर में सब्जी उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसानों को उनके उपज का सही दाम मिले। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए चावल खरीदी में की गई कटौती किसानों के प्रति अन्याय है। अब बायोमेट्रिक पद्धति से धान खरीदी का नियम केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।

यह किसानों को परेशान करने का नया तरीका है।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा की राज्य में सरकार बनने के साथ ही कृषि के क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। राज्य के सरकार अब किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी। विगत वर्ष 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपए किसानों को उसके उपज के लिए दिया गया। सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कार्यक्रम में श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य में किसानों की प्रगति के लिए नए-नए संसाधनों को अपनाया जा रहा है। नए मंडी भवन के बन जाने से अब राज्य के सभी मंडी सदस्यों को काम-काज में आसानी होगी। उन्होंने मंडी समिति के सदस्य द्वारा की गई विभिन्न मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की बात भी कही। समारोह में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, राज्य के सभी मंडी बोर्ड के अध्यक्ष और समिति के सदस्य, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्री कमलप्रीत सिंह, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड श्री यशवंत कुमार, आईजी श्री रतन लाल डांगी, प्रबंध संचालक गोधन न्याय मिशन डॉ. अय्याज फकीर भाई तंबोली आदि उपस्थित थे।

## लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा पर भड़के सीएम भूपेश

**रायपुर।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा पर निशाना साधा। भूपेश ने मिश्रा के उस बयान पर तंज कसा जो उन्होंने राहुल गांधी के चीन के लद्दाख की जमीन पर कब्जे वाले बयान के बाद कहा था। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने दावा किया था कि चीन ने लद्दाख की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है।

सीएम बघेल ने कहा कि आजकल सब कुछ सैटेलाइट से दिख रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि चीन ने अतिक्रमण किया है। भारत की सीमा और जमीन हड़प ली। बावजूद इसके उपराज्यपाल इसे मानने को तैयार नहीं है। एलजी किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं, यह किसी की भी समझ से परे हैं।

राहुल गांधी ने अपने हालिया लद्दाख दौरे के दौरान दावा किया कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि स्थानीय लोगों का भी तर्क है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की और कब्जा कर लिया, यह चिंता का विषय है। इस दावे को नकारते हुए एलजी मिश्रा ने कहा था कि चीन ने लद्दाख में एक वर्ग फुट जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। एलएसी पर हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल ऊंचा है। कोई भी लद्दाख की जमीन पर गलत मनसूबों के साथ अपने पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता।

## दंतेवाड़ा से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा

**रायपुर/जगदलपुर।** बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने आज 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से भापजा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रथ पर प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान जमकर भारत माता के जयकारे लगे। लोक नर्तकों ने अपने नृत्य से रथ का स्वागत किया।

दूसरी ओर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का जगदलपुर दौरा रद्द हो गया है। वो दंतेवाड़ा से शुरू हो रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे। बताया जाता है कि दक्षिण बस्तर समेत जगदलपुर में खराब मौसम की वजह से शाह का प्लेन अब तक दिल्ली से टेकआफ नहीं कर पाया है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि जगदलपुर में खराब मौसम की वजह से दिल्ली से शाह का प्लेन टेकऑफ नहीं कर सका है। ऐसे में ढाई बजे के बाद केंद्रीय मंत्री स्मति इरानी दंतेतवाड़ा पहुंच रही हैं। भाजपा की ओर से बताया गया है कि स्मृति ईरानी मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगी। जनसभा को संबोधित करेंगी। हालांकि वो अभी तक नहीं पहुंची है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि वो जगदलपुर से या किसी अन्य जगह से रथ पर सवार होंगी।दूसरी ओर ये भी चर्चा है कि कहीं खराब मौसम के कारण उनका दौरा भी रद्द हो सकता है।

दंतेवाड़ा से गीदम तक परिवर्तन यात्रा में बीजेपी नेता रथ में ही सफर करेंगे। रथ पूरी तरह से हाईटेक सुविधाओं से लैस है।रथ के साथ एलईडी स्क्रीन वाले प्रचार वाहन भी तैयार किए गए हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी घुमाने का निर्णय लिया है। यानी कि 108 पेज का आरोप पत्र का सारांश पत्रक भी लोगों को बांटा जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोक नर्तकों ने अपने नृत्य से कार्यक्रम में समां बांधा। रथ का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। लोग अमित शाह को सुनने पहुंचे थे, लेकिन उनका दौरा स्थगित होने पर उन्हें मायूसी हाथ लगी।

## रायगढ़ का 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या है मिजाज

**रायगढ़।** छत्तीसगढ़ के रायगढ़ को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। रायगढ़ में चार विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें रायगढ़, खरसिया, लैलूंगा, धरमजयगढ़ हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने रायगढ़ की चारों विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। रायगढ़ विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां पर पिछली बार 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश नायक ने जीत दर्ज की थी।

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 25 हजार 722 महिला मतदाता हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 27 हजार 343 है। 19 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। रायगढ़ विधानसभा में कुल 2 लाख 53 हजार 84 मतदाता हैं। पिछले चुनाव से लेकर अब तक पांच सालों में 31 हजार 156 मतदाता बढ़ें हैं।

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2003 के चुनाव में बीजेपी के विजय अग्रवाल ने कांग्रेस कद्दावर नेता कृष्ण कुमार गुप्ता को हराया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शक्राजीत नायक ने अपनी जीत दर्ज की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रोशन लाल अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रकाश नायक ने 14580 वोट से अपनी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में प्रकाश नायक को 69,062 वोट मिला था, वहीं भाजपा के स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल ने 54480 वोट प्राप्त किया था, तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी विजय अग्रवाल ने 42914 वोट पाया था।

### गुटबाजी बिगाड़ती है खेल

रायगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां गुटबाजी की शिकार होती रहीं हैं। कांग्रेस पार्टी बीते 1 हफ्ते से विधायक प्रत्याशियों का फार्म जमा कर रही है, जिसमें अब तक 21 प्रत्याशियों ने अपना फार्म जमा किया है। वहीं बीजेपी की बात करें, तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ओपी चौधरी, सुनील रामदास, विजय अग्रवाल, गुरपाल भल्ला जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। मगर शहर में चर्चा है कि ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन शहर में ओपी चौधरी के स्थानीय नहीं होने की भी चर्चा है। जिससे ओपी चौधरी को रायगढ़ सीट से चुनाव जीतने में काफी दिक्कतें आ सकती है। लोगों का मानना है कि यहां यदि आप चौधरी चुनाव लड़ते हैं, तो वर्तमान विधायक प्रकाश नायक फिर से जीत सकते हैं।

### मुद्दे और समस्याएं

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोयले का भंडार है। राजस्व के मामले में भी रायगढ़ प्रदेश को आर्थिक रूप से सहयोग करता है। फिर भी यहां बुनियादी सुविधा जैसे पानी और सड़कें आज भी खराब हैं। कोयले की खान होने के कारण रोजाना ट्रकों का आना जाना चलता रहता है। उस लिहाज से सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। जिससे आए दिन रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके साथ ही रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र हाथी के हमले से प्रभावित हैं। बीते तीन दशक से रायगढ़ में कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं देखा गया, जो मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देकर सुधार लाया हो।

### 2018 में कांग्रेस ने छीनी सीट

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रकाश नायक ने 69062 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने 14580 वोट के बड़े अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। बीजेपी के प्रत्याशी रहे स्व रोशन लाल 54482 वोट मिला था। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विजय अग्रवाल को 42912 वोट मिला था। विजय अग्रवाल बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी प्रत्याशी को हर का सामना करना पड़ा।

रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर द्वितीय तल, भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर
न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन :- (0771) 2536188,
पी.बी.एक्स.2533788 फैक्स 2534688

"उद्घोषणा"

क्रमांक 12083/ आर.सी./रा.वि.प्रा./2023
रायपुर दिनांक 08/9/23

प्राधिकरण की कटोरातालाब योजनान्तर्गत 1 श्रीमती शारदा देवी चांडक पति श्री बृजगोपाल चांडक 2.श्रीमती कुसुम चांडक पति श्री श्यामसुन्दर चांडक 3 श्री शैलेश कुमार चांडक पिता श्री बृजगोपाल चांडक 4. श्री हरगोपाल चांडक पिता स्व. रामनारायण चांडक को भूखण्ड क्रमांक सी-35/1 क्षेत्रफल 2895 वर्गफुट 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटित है। आबंटितीयों में से एक सह आबंटिती श्री हरगोपाल चांडक पिता स्व. रामनारायण चांडक की। मृत्यु दिनांक 23.03.2017 को हो जाने के कारण सह आबंटिती के वारिसान पत्नि श्रीमती विमला चांडक पति स्व. हरगोपाल चांडक, निवासी-जवाहर नगर, रायपुर (छ.ग.) द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त उत्तराधिकारी नामांतरण अनुमति प्रदान किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा हो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर प्राधिकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हो कर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति/दावा प्राप्त नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही संपादित की जावेगी। निर्धारित तिथि के बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राहय नहीं होगा।

जारी दिनांक.....

राजस्व अधिकारी (तहसीलदार)
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग.)

# भारत के बढ़ते रसूख का सबको अहसास

**हर्ष वी. पंत**

किसी राष्ट्र की यात्रा में ऐसे पल आते हैं, जब वैश्विक मंच पर उसका उभार कुछ इस तरह से होता है कि उसमें शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। भारत की जी20 की अध्यक्षता ऐसा ही ऐतिहासिक पल लेकर आई है। भारत जी20 शिखर बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति हासिल कर पाएगा या नहीं, इस सवाल को लेकर उदासी के सारे बादल तब अचानक छंट गए, जब बैठक समाप्त होने के काफी पहले ही सहमति का दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया गया। भारत का औसत प्रदर्शन देखने के हम इस कदर आदी हो चुके हैं कि जब देश ने अपेक्षाओं की सारी हदें तोड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन किया तो उस खबर को जज्ब करने में भी हमें थोड़ा वक्त लगा। यहां बात सिर्फ नई दिल्ली घोषणा पर बनी सहमति की नहीं, उस पूरे ऐटिट्यूड की है, जिससे जी20 की यह पूरी प्रक्रिया संचालित की गई। शिखर बैठक में भारत ने अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षा और मेगा डिप्लोमेसी की क्षमता को फिर से साबित किया। जी20 की इस प्रक्रिया के दौरान समानांतर रूप से दो संवाद साथ-साथ चल रहे थे। एक तरफ देश के अंदर आम हिंदुस्तानी घरेलू और दूसरे देशों के बीच लगातार धुंधली पड़ती रेखा को देख रहा था और इस तरह देश के बाहरी प्रभाव को बेहतर ढंग से महसूस कर पा रहा था। दूसरा संवाद बाकी पूरी दुनिया से था, जो अतीत में अक्सर वैश्विक मंचों पर नेतृत्व करने की भारत की इच्छा और क्षमता पर सवाल उठाती रही थी। सच पूछिए तो पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वैश्विक व्यवहार में महत्वाकांक्षा की नई भावना भर दी है। उनकी द्विपक्षीय कूटनीति तो जगजाहिर रही ही है, जी20 ने उन्हें और भारत को सीधे एक बड़े और व्यापक मंच पर ला दिया। इसमें नई दिल्ली को बड़ी ताकतों के आपसी संघर्ष से उपजे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय माहौल से भी मदद मिली। तेजी से उभरते वैश्विक शक्ति संतुलन के दबाव के कारण मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों की कमजोरियां पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक विकास का वह अजेंडा खतरे में पड़ गया, जिसके लिए महामारी के बाद के समय में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बेकरार था। भारत अपने नेतृत्व का सिक्का जमाने के लिए उसने जी20 की अपनी अध्यक्षता का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस बात से खास मतलब नहीं था कि जी20 का मंच अतीत में खास प्रभावी नहीं रहा है। नई दिल्ली को अपनी भूमिका सही ढंग से निभानी थी और उसने निभाई। वैश्विक राजनीति की संरचनात्मक वास्तविकताएं कोई भारत की बनाई हुई नहीं हैं, न ही भारत इकतरफा तौर पर उन्हें बदल सकता है। लेकिन उसे ग्लोबल गवर्नेंस का अपना अजेंडा सामने रखने का कोई रास्ता तलाशना था। और, यह काम उसने पूरे भरोसे के साथ किया; टकराव और विकास के अजेंडे के बीच की कड़ी पर फोकस बढ़ाते हुए, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स हासिल करने में मिल रही नाकामियों को रेखांकित करते हुए, अपने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक जनकल्याण के साधन के रूप में पेश करते हुए, मल्टीलैटरल डिवेलपमेंट बैंक में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर बढ़ाते हुए, कम और मध्य आय वाले देशों पर कर्ज के बोझ को रेखांकित करते हुए और ग्लोबल साउथ को अपनी ग्लोबल गवर्नेंस इनीशटिव्स के केंद्र में रखते हुए।

# आसान नहीं है एक राष्ट्र, एक चुनाव की राह

**जयसिंह रावत**

गत 11 अगस्त को संसद का मासून सत्र सम्पन्न हो जाने के बावजूद केन्द्र सरकार का अचानक 18 से 22 सितम्बर तक संसद का विशेष-सत्र बुलाना एक बड़े राजनीतिक धमाके का स्पष्ट संकेत है। लेकिन साथ ही ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' की व्यवस्था की संभावनाओं पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने से लगता है कि सरकार विशेष सत्र में एक साथ चुनाव कराने की संवैधानिक व्यवस्था करने जा रही है। इसके अलावा भी ''इंडिया'' एलायंस को ढेर करने के लिए समान नागरिक संहिता और महिला आरक्षण बिल जैसे राजनीतिक ब्रह्मास्त्र भी चलाए जा सकते हैं।

बहरहाल, चर्चा तो एक साथ चुनाव की ही है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और संघीय देश में ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' (ओएनओई) कानून लाना जितना आकर्षक लग रहा है उतना ही अधिक जटिल भी है। इस विचार को व्यवहारिक धरातल पर उतारने में भारत सरकार को महत्वपूर्ण व्यावहारिक, संवैधानिक और राजनीतिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में संवैधानिक प्रावधानों की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के संविधान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव का प्रावधान नहीं है। इस विचार को सक्षम करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति और एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। राज्य विधान सभाओं और लोकसभा के लिए निश्चित शर्तें समकालिक नहीं हैं। इन शर्तों के समन्वय के लिए दोनों स्तरों पर संवैधानिक संशोधन और कानूनी बदलाव की आवश्यकता होगी। संविधान के जानकारों के अनुसार इसके लिए कम से कम संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा, जिनमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 175 शामिल हैं।

अनुच्छेद 83 खंड (2) के तहत लोकसभा का कार्यकाल ठीक 5 साल तय किया गया है। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। भारत में किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 172 द्वारा निर्धारित किया गया है। यह अनुच्छेद

निर्दिष्ट करता है कि राज्य विधान सभा का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष होगा। लेकिन इसे कुछ परिस्थितियों में राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है, जैसे कि जब विधानसभा बहुमत का विश्वास खो देती है या जब राज्यपाल इसके विघटन की सिफारिश करता है।

संविधान आपातकाल की घोषणा की स्थिति में विधानसभा के कार्यकाल के विस्तार की भी अनुमति देता है। इसी अनुच्छेद में प्रावधान है कि जब आपात् की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। राज्य की संवैधानिक मशीनरी के खराब होने की स्थिति में केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 में प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर राज्य के प्रशासन का नियंत्रण ग्रहण करता है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। लेकिन अब इस अनुच्छेद का इस्तेमाल आसान नहीं रह गया है। केंद्र शासित प्रदेशों, जिनकी अपनी विधान सभाएं नहीं हैं, की विशिष्ट स्थिति को समायोजित करने के लिए भी आवश्यक प्रावधान करने होंगे। अनुच्छेद 324 में संशोधन कर एक साथ चुनावों के समन्वय के लिए चुनाव आयोग को अतिरिक्त अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ सशक्त बनाना होगा ताकि आयोग समय से पहले बिना राज्य सरकार की सहमति से भी चुनाव तिथियां घोषित कर सके।

आजादी के बाद पहले चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। लेकिन दलबदल, राजनीतिक अस्थिरता तथा अनुच्छेद 356 के बार-बार इस्तेमाल के कारण एक साथ चुनाव का क्रम टूटता गया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार समय से पहले गिरती रही है और विधानसभा नई बहुमत की सरकार चुनने की स्थिति में नहीं रहीं। अब अविश्वास प्रस्तावों और विधान सभाओं के विघटन से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता भी होगी। चुनाव के समय में बदलाव के लिए दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) में संशोधन भी करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में संवैधानिक संशोधनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों द्वारा समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसी आम सहमति हासिल करना और संविधान में सफलतापूर्वक संशोधन करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।

एक साथ चुनाव के पक्ष में धन की बचत का तर्क भी दिया जा रहा है लेकिन भारत जैसे विशाल और आबादी वाले देश में चुनाव कराने के लिए व्यापक साजो-सामान योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव होने से भारत के चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी पर भारी दबाव पड़ेगा। देश के हर कोने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), प्रशिक्षित कर्मियों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक कठिन काम होगा। नई व्यवस्था से राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है और क्षेत्रीय चिंताओं की उपेक्षा हो सकती है, जो संभावित रूप से संघवाद को कमजोर कर सकती है। एक साथ चुनाव को लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक सहमति हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। विपक्षी दल वैसे ही इस विचार से विचलित नजर आ रहे हैं। जिन परिस्थितियों में यह कदम उठाया जा रहा है उनसे संदेह स्वाभाविक भी है। एक विचार यह भी है कि कुछ राज्यों में, व्यवहार्यता का आकलन करने और चुनौतियों से निपटने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह काम शुरू किया जा सकता है। फिलहाल इसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। इसलिए आम चुनाव अप्रैल से मई के बीच संभावित हैं। लेकिन केन्द्र सरकार उससे पहले भी चुनाव करा सकती है, ताकि अधिक से अधिक राज्यों के चुनाव भी लोकसभा के साथ हो सकें।

कम से कम दस राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2024 में आम चुनावों के लिए निर्धारित समय से पहले या उसके आसपास समाप्त हो रहा है। जबकि पांच राज्यों - मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होने की संभावना है। जबकि मीजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव दिसम्बर से लेकर जनवरी 2024 तक होने हैं। सामान्यत: समय से पहले चुनाव कराने की सिफारिश केन्द्रीय और राज्यों की कैबिनेट करती है और फिर निर्वाचन आयोग चुनाव तिथियां घोषित करता है। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय है। चूंकि निर्वाचन आयोग कहने भर को स्वायत्तशासी है मगर व्यवहार में वह केन्द्र सरकार का ही एक विभाग है जो कि सामान्यत: केन्द्र सरकार की सुविधानुसार ही काम करता है। इसलिए जून में होने वाले राज्यों के चुनाव भी समय से पहले लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं।

वर्तमान में 10 राज्य भाजपा शासित हैं और 4 एनडीए शासित हैं। चूंकि भाजपा ने चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ने हैं, इसलिए सत्ताधारी भाजपा चाहे तो इन राज्यों के चुनाव भी राज्य सरकारों की सहमति से समय से काफी पहले लोकसभा के साथ करा सकती है। वर्तमान में कांग्रेस शासित 4 राज्यों में से हिमाचल और कर्नाटक में और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और दिल्ली के साथ ही पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव समय से पहले कराने के लिये केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 में संशोधन करा सकती है। आम सहमति का अभाव भारत जैसे विविधतापूर्ण और संघीय देश में यह एक जटिल उपक्रम है। आम सहमति हासिल करने, संवैधानिक और कानूनी बाधाओं को दूर करने और एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में दृढ़ इच्छा शक्ति की तो कमी नहीं मगर आम सहमति का नितान्त अभाव साफ नजर आ रहा है।

**भारतीय ज्ञान परंपरा....**

# पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-4)

**गतांक से आगे...**

वेद एवं उपनिषद् में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, उसी (परमात्मतत्त्व ) की ये स्वाध्याययुक्त.

इस महायज्ञ का ज्ञान ही अश्वमेध यज्ञ है। इसके आश्रय से ही वे (ज्ञानीजन) ब्रह्मज्ञान का आचरण करते हैं। पूर्व में वर्णित समस्त ब्रह्मयज्ञ कर्म ही मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं

ब्रह्मपुत्र ने पुन: कहा-हंस से सम्बन्धित ज्ञान का प्राकट्य हो गया है। ऐसा श्रवण कर स्वयंभू तिरोहित हो गये। इस उपनिषद् में जिस हंस ज्योति का वर्णन किया गया है, वही रुद्र है और संसार से उद्धार करने वाला प्रणव (ओंकार) ही पशुपति (ब्रह्म) है, उसे ऐसा जानो ॥ 32॥

जो मनुष्य अपने आत्मिक ज्ञान से ब्रह्म के समान हो गया हो, फिर उसके संदर्भ में कहने के लिए क्या शेष रह जाता है ? ज्ञानी मनुष्य अपना सम्पूर्ण समय ब्रह्मचर्चा एवं उपासना में ही व्यतीत करते हैं। जब हंस एवं आत्मा में एकात्मता स्थापित हो जाती है, तो फिर प्रजा कहाँ हो सकती है ? ॥ 2 ॥ अन्त: प्रणवनादाख्यो हंस: प्रत्ययोधक: अन्तर्गतप्रमागूढं ज्ञाननालं विराजितम् ॥ 3 ॥

अन्त:करण से नि:सृत होने वाले प्रणव रूपी नाद से जो हंस ज्ञात होता है, वही सम्पूर्ण ज्ञान का बोध कराने वाला है। अन्त में अनुभवगम्य गूढ़ ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत् के ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ 3 ॥

तीन अंग, तीन शिखा एवं दो या तीन मात्राओं में उसकी संख्या (आकृति) ज्ञात होती है। जब इस प्रकार से वह अन्तर्धान हो जाता है, तब इस गूढ़ आत्मा का ज्ञान बाह्य जगत् में भी प्रमाण के रूप में प्रकट होता है ॥

जगत् के सूत्ररूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके स्वयमेव ब्रह्म के लक्षणों से युक्त होना चाहिए तथा निरन्तर हंस रूपी सूर्य का प्रणव सहित ध्यान करते रहना चाहिए, यही ज्ञानीजनों का उपदेश है ॥

इस प्रकार से विशेष ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात् ही ज्ञान सागर के पार पहुँचा जा सकता है। स्वयं भगवान्

[ अध्यात्म क्षेत्र में जड़-चेतन दोनों प्रकार के ज्ञान के अतिवाद को उचित नहीं माना गया है, जैसा कि ईशोपनिषद् (9) में अन्धं तम: प्रविशन्ति ..... इत्यादि मन्त्र में केवल विद्या की उपासना करने वालों को भी अन्धकार में फँस जाने की बात कही गई है। यहाँ ज्ञान को डुबाने वाला सागर तथा उससे पार जाने की बात उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर ही कही गयी प्रतीत होती है।]

यही भगवान् शिव सभी लोगों के मन को प्रेरित एवं संतुलित नियमित करने वाले हैं, जिसके प्रभाव से मन विषयों में गतिशील होता है। प्राण चेष्टा रत रहते हैं तथा वाणी उच्चारण का कार्य करती है ॥ उन्हीं भगवान् की प्रेरणा से चक्षु रूपों दृश्यों को देखते हैं, कान श्रवण करते हैं तथा अन्य समस्त इन्द्रियाँ भी उन्हीं से प्रेरित हो रही हैं। वे निरन्तर अपने-अपने विषयों के उद्देश्य में प्रवृत्त होती रहती हैं। यह विषयों में प्रवृत्त होना ही मायारूप है, यह स्वभाववश नहीं होता, माया द्वारा ही होता है॥ **क्रमश:**

# कुप्प. सी. सुदर्शन

**प्रवीण दुबे**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर समझना है तो पूर्व सरसंघचालक श्री कुप्प. सी. सुदर्शन के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन कीजिए, उनके जीवन में वह सारी बातें निहित हैं जो संघ में हैं। कई बार संघ पर तरह-तरह के आरोप लगते रहते हैं। कोई संघ को सांप्रदायिक कहता है तो कोई कट्टरवादी कोई इसे एक खास राजनैतिक दल के लिए कार्य करने वाला संगठन निरुपित करता है। इन सारे आरोपों का जवाब अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सुदर्शन ने दिया वे कभी भी इस विवाद में नहीं पड़े कि संघ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं परन्तु उन्होंने एक-एक आरोप का जवाब अपने कार्यों से दिया। अभी कुछ ही दिन पूर्व की घटना है जब भोपाल में ईद के दिन सुदर्शन ने ईद की नमाज पर मस्जिद में जाकर मुसलमानों को ईद की बधाई देने की इच्छा जाहिर करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। इतना ही नहीं संघ में सुदर्शन ही जी थे जिन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह प्रसंग कोई मामूली घटनाक्रम नहीं कहा जा सकता वह भी संघ के परिपेक्ष्य में, यह जवाब है उन लोगों को जो संघ को सांप्रदायिक और कट्टरवादी कहकर उसे अछूत मानते रहे हैं और संघ को समाज से काटने का प्रयास करते रहे हैं। वास्तव में संघ न तो सांप्रदायिक है न कट्टरवादी वह तो सभी देशवासियों को राष्ट्रप्रेम जागृत करने का संदेश देता

है। यदि संघ सांप्रदायिक होता तो संघ के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त होने वाले सुदर्शन न तो ईद की नमाज पर मस्जिद में जाकर मुसलमानों को बधाई देने की बात करते और न ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसे संगठन का वे निर्माण करते। सुदर्शन का तर्क था कि ईश्वर की इबादत से कौन सा मजहब रोकता है। इसके बाद सुदर्शन ने शहरकाजी और कुछ अन्य मित्रों के घर जाकर ईद की मुबारकवाद दी। मुझे अच्छी तरह याद है 15 अगस्त 2010 का वह दिन जब सुदर्शन जी ग्वालियर प्रवास पर थे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा अखंड भारत दिवस के अवसर पर 'मादरे वतन हिन्दुस्तान से मोहब्बत मुसलमानों का दिली जज्बा' विषय पर सुदर्शन का व्याख्यान था। इस व्याख्यान का एक-एक शब्द आज भी याद आता है कितना गहरा अध्ययन और चिंतन था उनका वे विषय पर एक घंटे बोले और वे जो बोले शायद ऐसे लोगों को पसंद न आया जो संघ को सांप्रदायिक और कट्टरवादी से ज्यादा कुछ नहीं मानते। सुदर्शन ने उस व्याख्यान में कहा था भारत विभाजन के लिए लोग मोहम्मद अली जिन्ना को दोष देते हैं लेकिन यह आधा सच है। जानकार यह आश्चर्य होगा कि भारत विभाजन में महात्मा गांधी की भूमिका थी। अगले दिन समाचार पत्रों में सुदर्शन के इस व्याख्यान का तरह-तरह से विश्लेषण छपा और सभी ने इस बात के लिए सुदर्शन की सराहना की कि उन्होंने इतने संवेदनशील विषय को इतने सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया। वह सुदर्शन ही थे जिन्होंने कई मौकों पर अपनी बेबाक राय से हलचल पैदा की और तमाम विरोधों के बावजूद अपनी बात पर कायम ही नहीं रहे बल्कि अपने तर्कों और तथ्यों से उसे सही भी ठहराया।

सुदर्शन एक महान चिन्तक और लेखक भी थे शायद ही कोई विषय ऐसा हो जिस पर सुदर्शन जी का गहरा अध्ययन न हो। तथ्यों के साथ वे अपनी बात को रखते थे और जो सही होता था वह कहने में नहीं घबराते थे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं परन्तु उनका जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक संघ को सच्चे और निष्ठावान स्वयंसेवक का जीवन कैसा होता है। उनके जीवन परिचय को पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

उनकी दिनचर्या स्वयंसेवकों के लिए ही नहीं सम्पूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायी थी। अंतिम सांस लेने से पूर्व भी सुदर्शन ने अपने नित्य कार्य यथावत पूर्ण किए वह प्रातः सैर पर गए लौटकर शाखा पर प्रार्थना की और योगासन, प्राणायाम करते समय अपनी देह त्याग दी। वास्तव में उनका जीवन व्यक्ति निर्माण की कुंजी था जो युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा।

# कूटनीतिक जगत का महारथी बनकर उभरा भारत

**समीर चौगांवकर**

जी 20 का ऐतिहासिक आयोजन भारत के लिए कई प्रकार की कूटनीतिक सफलताओं के साथ संपन्न हो गया। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जिस भव्य स्तर पर किया गया था उसकी कूटनीतिक उपलब्धियां भी उससे कमतर नही हैं। यह वह समय है जब रूस और अमेरिका के संबंध बेहद बुरे दौर में है। चीन की आक्रामक आर्थिक नीति के कारण अमेरिका और भारत दोनों चीन को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। तब जी20 के संयुक्त घोषणा पत्र के लिए रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस का एक साथ आना और 37 पेज के संयुक्त व्यक्तव्य के सभी 87 पैरेग्राफ से सभी का सहमत हो जाना इस बात को दर्शाता है कि भारत ने केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करने में ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी नई ऊंचाई हासिल कर ली है। जी20 के 37 पेज के संयुक्त व्यक्तव्य के लिए मोदी की टीम ने कितनी मेहनत की इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसके लिए सभी देशों को सहमत करने के लिए 300 बैठकें और 200 घंटे से ज्यादा बातचीत की गयी। सभी ताकतवर और परस्पर विरोधी देशों को एक एजेंडे में शामिल करने के लिए अतीत के उन मुद्दों को ध्यान से पढ़ा गया जिस पर कभी न कभी विपरीत देश सहमत हुए थे, या उन्होंने कभी सुरक्षा परिषद और मानव अधिकार परिषद में व्यक्तव्य दिए थे। उनके दिए बयानों के आधार पर टीम मोदी ने नई शब्दावली तैयार की।

जी20 की अध्यक्षता कर रहे भारत के सामने चुनौती थी कि पिछले साल बाली में जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी थी या तो उन्हें छोड़ दिया जाए

या उन्हें नए सिरे से नई शब्दावली के साथ पेश कर सर्व सहमति बनाई जाए। भारत ने नई शब्दावली का मार्ग चुना और मोदी मैजिक के दम पर भारत के तैयार किए हुए प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न आने से जी20 शिखर सम्मेलन के महत्व को कम करके दिखा रहे चीन को भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक कॉरिडोर डील ने तगड़ा जवाब दिया है। चीन लगातार पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि चीन के नेतृत्व में कुछ समय पहले ही सउदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता पश्चिम एशिया में भारत के हित को प्रभावित करने के रूप में देखा जा रहा था। जी20 बैठक में भारत ने मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सउदी अरब के क्राउन प्रिंस की गर्मजोशी भरी मुलाकात करवाकर कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली है।

चीन के बढ़ते प्रभाव और दुनिया को उससे मिल रही चुनौती से सामना करने के लिए भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल से इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनामिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर महत्वपूर्ण देशों को शामिल कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत, यूएई, सउदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ यूरोपियन यूनियन के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। इस कॉरोडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान के आवागमन में करीब 40 प्रतिशत समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट के बनने के बाद 14 दिन की बचत होगी। भारत के पहल से बने इस इंडिया- मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस सम्मेलन की सफलता की बात की जाए तो 37 पेज के घोषणा पत्र में 83 पैराग्राफ को पूर्ण रूप से सभी सदस्यों का स्वीकारना एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और 15 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को गति और रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील की संभावना बढ़ गई है। ब्रिटेन से भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द चाहता है। इस बैठक के बाद उम्मीद है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर नवंबर या दिसंबर तक मुहर लग सकती है।

अफ्रीकी यूनियन को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करवाने में भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करवाना भारत की सधी हुई कूटनीति की मिसाल है। अफ्रीकी यूनियन के 55 देश भारत को इस बात का श्रेय दे रहे हैं। चीन अफ्रीकी देशों में जिस तेजी से पैर पसार रहा था, उसे रोकने के लिए भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जी20 में शामिल कर चीन को तगड़ा झटका दिया है। हालांकि चीन ने भी भारत के इस प्रस्ताव पर सहमति दर्शाई थी। मोदी जिन चुनौतियों को दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, उन चुनौतियों पर जी20 के देशों को राजी करने पर सफल रहे हैं। मोदी की पहल का परिणाम है कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलेपमेंट पर काम करने पर सहमत हो गये। यूएन चार्टर के मुताबिक काम करने तथा पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के साथ बायोफ्यूल एलांयस बनाने पर भी सहमति बनी, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्राजील फाउंडर मेम्बर के रूप में शामिल हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रूप में विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ जोड़ने में भारत सफल रहा है।

जी20 के इस शिखर सम्मेलन में भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता यह रही कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन की अनुपस्थिति के बाद भी भारत ने अमेरिका को हावी होने का मौका नहीं दिया और न ही भारत का पलड़ा अमेरिका की और झुका हुआ नजर आया। भारत इस बात को समझता है कि चीन वह देश है जिसके कारण अमेरिका भारत को रिझा रहा है और भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताने की कोशिश कर रहा है। आक्रामक चीन अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए एक खतरा बन गया है। इसी वजह से अमेरिका को जापान से लेकर ताइवान तक और आस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण कोरिया तक अपने सहयोगी देशों की हिफाजत करने के लिए भारत के सहयोग की जरूरत है। चीन को सबसे बड़ी चुनौती मान रहा अमेरिका यह पक्का करना चाहता है कि चीन को संतुलित करने के लिए एक असरदार देश उसके पास हो जिस वजह से अमेरिका भारत की और देख रहा है। कूटनीति की भाषा में इसे कॉस्टली सिग्नलिंग कहते हैं। भारत भी इस बात को समझता है कि चीन

**हिन्द स्वराज्य**

# हिन्दुस्तान की दशा-2 (भाग-7)

**गतांक से आगे...**

अन्त में, हिन्दू अहिंसक और मुसलमान हिंसक है, यह बात अगर सही हो तो अहिंसक का धर्म क्या है? अहिंसक को आदमी की हिंसा करनी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अहिंसक के लिए तो राह सीधी है। उसे एक को बचाने के लिए दूसरे की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। उसे तो मात्र चरण- वंदना करनी चाहिए, सिर्फ समझाने का काम करना चाहिए। इसी में उसका पुरुषार्थ है। लेकिन, क्या तमाम हिन्दू अहिंसक हैं? सवाल की जड़ में जाकर विचार करने पर मालूम होता है कि कोई भी अहिंसक नहीं है, क्योंकि जीव को तो हम मारते ही हैं। लेकिन इस हिंसा से हम छूटना चाहते हैं, इसलिए अहिंसक (कहलाते हैं। साधारण विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से हिन्दू मांस खाने वाले हैं, इसलिए वे अहिंसक नहीं माने जा सकते। खींच-तानकर दूसरा अर्थ करना हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है जब ऐसी हालत है तब मुसलमान हिंसक और हिन्दू अहिंसक हैं इसलिए दोनों की नहीं बनेगी, यह सोचना बिलकुल गलत है। ऐसे विचार स्वार्थी धर्मशिक्षकों, शास्त्रियों और मुल्लाओं ने हमें दिये हैं और इसमें जो कमी रह गयी थी उसे अंग्रेजों ने पूरा किया है। उन्हें इतिहास लिखने की आदत है; हरएक जाति के रीति-रिवाज जानने का वे दंभ करते हैं। ईश्वर ने हमारा मन तो छोटा बनाया है, फिर भी वे ईश्वरी दावा करते आये हैं और तरह-तरह के प्रयोग करते है। वे अपने बाजे खुद बजाते हैं और हमारे मन में अपनी बात सही होने का विश्वास जमाते हैं। हम भोलेपन में उस सब पर भरोसा कर लेते हैं। जो टेढ़ा नहीं देखना चाहते वे देख सकेंगे कि कुरान शरीफ में ऐसे सैकड़ों वचन हैं, जो हिन्दुओं को मान्य हों; भगवद्गीता में ऐसी बातें लिखी हैं कि जिनके खिलाफ मुसलमान को कोई भी एतराज नहीं हो सकता। कुरान शरीफ का कुछ भाग मैं न समझ पाऊँ या कुछ भाग मुझे पसंद न आये, इस वजह से क्या मैं उसे मानने वाले से नफरत करूँ? झगड़ा दोसे ही हो सकता है। मुझे झगड़ा नहीं करना हो, तो मुसलमान क्या करेगा? और मुसलमान को झगड़ा न करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हवा में हाथ उठाने वाले का हाथ उखड़ जाता है। सब अपने-अपने धर्म का स्वरूप समझकर उससे चिपके रहें और शास्त्रियों व मुल्लाओं को बीच में न आने दें, तो झगड़े का मुँह हमेशा के लिए काला ही रहेगा। **क्रमश: ...**

# अदालतों की लताड़ ममता सरकार को आदत-सी पड़ गई

**योगेंद्र योगी**

कानून-व्यवस्था से खिलवाड़, भ्रष्टाचार और वोट बैंक के लिए सरेआम तुष्टिकरण जैसी नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जितनी लताड़ खाई है, उतनी देश के किसी अन्य राज्यों की सरकारों ने शायद ही कभी खाई हो। आश्चर्य की बात यह है कि अदालतों से मिली मुकदमों में हार और फटकार के बावजूद ममता सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। ममता सरकार का रवैया संविधान के कायदे-कानूनों का उल्लंघन करना रहा है। विपक्षी दलों ने ममता सरकार की इस प्रवृत्ति पर कभी पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया। सत्ता में होने का बेजा फायदा उठाने की लगातार बढ़ती पुनरावृत्ति पर अदालतों ने अंकुश लगाया है। ममता सरकार का रवैया ऐसा रहा है जैसे पश्चिम बंगाल भारत के संवैधानिक दायरे से अलग कोई देश हो।

नया मामला पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों में भर्ती घोटाले से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य मामलों की तरह इसमें भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय मामले में दखल देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्थानीय निकाय भर्ती और शिक्षक भर्ती घोटाले में लिंक है। इन दोनों मामले में वो सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ ने कथित घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर राहत देने से इंकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने इस दलील को मान लिया कि ये सब बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सीबीआई जांच काफी आगे पहुंच गई है। अब इसमें दखल देते हुए रोकना उचित नहीं है। इससे पहले भी ममता सरकार भ्रष्टाचार सहित कई दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट मिली लताड़ और हार के बावजूद ममता सरकार के रवैये में कोई विशेष सुधार नहीं आया। सरकार की ना तो कार्यशैली बदली और न ही तृणमूल कांग्रेस में कोई तब्दीली नजर आई। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की बिना यूपीएससी के दखल के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के मामले में कहा था कि हमारे पिछले आदेश में

बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने बार-बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

सुप्रीम कोर्ट एक पुराने आदेश में कह चुका है कि हर राज्य को डीजीपी की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से योग्य अधिकारियों की लिस्ट लेनी होगी। उसी लिस्ट में से चयन करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि यह व्यवस्था गलत है। राज्य सरकार को चयन का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को लेकर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की राज्यों सरकारों को कोई आपत्ति नहीं जताई। इन मामलों की तरह ही इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने साफ कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने एनआईए को जांच ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यह निर्देश राजनीतिक रूप से पारित किया गया था। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की तरफ से याचिका डाली गई थी। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रामनवमी समारोह के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिबपुर और हुगली जिलों के रिशरा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था। ममता सरकार को कानून को चुनौती देने के साथ भ्रष्टाचार जैसे मामलों में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। ऐसे ही एक मामले में सरकार ने कोर्ट का रुख किया किन्तु शीर्ष अदालत में जाना सरकार के काम नहीं आ सका। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की अपील पर सुनवाई में दिया। जिसमें हाईकोर्ट के ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो को कथित घोटाले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी।

ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल को कैसे देश के बाहर का हिस्सा समझती है, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी से बैन हटाने के निर्णय साबित होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है। कुछ इसी तरह का रवैया तमिलनाडु सरकार का भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी दे केरल स्टोरी से बैन हटाने का निर्देश दिया था। बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का ये सकारात्मक दायित्व है। इस तरह तो आप समाज में किसी भी 13 लोगों को चुन सकते हैं। अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहां फिल्म बैन करिए, जो लोग ना देखना चाहें वो ना देखें। वे कुछ भी प्रतिबंध लगाने को कहेंगे। खेल या कार्टून दिखाने को छोड़कर नियमों का उपयोग जनता की सहनशीलता पर लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। अन्यथा सभी फिल्में इसी स्थान पर खुद को पाएंगी।

ममता सरकार शायद यह भूल गई कि बहुमत से सत्ता में आने का मतलब यह नहीं है कि देश की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा सके। कानून को अपनी सुविधा और फायदे के लिए तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता। ममता सरकार ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से मिली हार से कोई पाठ पढ़ा होता तो ऐसे मामलों में शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। एकता का सुर अलाप रहे विपक्षी

# इंडिया दैट इज भारत, संविधान में खुले हैं दोनों विकल्प

**हरबंश दीक्षित**

अपने देश के नाम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। शुरुआत एक निमंत्रण पत्र को लेकर हुई, जिसे राष्ट्रपति की ओर से लिखा गया है। उसमें राष्ट्रपति के पद नाम को भारत गणतंत्र का राष्ट्रपति लिखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि इसके लिए पारंपरिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया का इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद- 1 में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, दोनों है और इसमें से किसी भी नाम से इसे संबोधित किया जा सकेगा। आम तौर पर किसी घटना या कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए इंडिया या भारत शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन, अतुल्य भारत से राष्ट्रीय गौरव के बारे में जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के नाम से पोर्टल तथा दूसरी सरकारी गतिविधियां भी भारत नाम से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी नाम वाली गतिविधियों या कार्यक्रमों का भी जब हिंदी अनुवाद किया जाता है, तो वहां इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल भारत। भारत सरकार के राजपत्र को अंग्रेजी में गजट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का राजपत्र कहा जाता है। हर संप्रभु राष्ट्र को अपना नाम रखने का अधिकार होता है। हमारे देश को अलग-अलग समय पर अलग-अलग नाम से संबोधित किया जाता रहा। वर्ष 1857 के बाद जब ब्रिटेन की सरकार ने पूरे देश का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया, तो एकरूपता बनाए रखने के लिए इंडिया नाम पर मुहर लग गई। कानूनों में भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे 1861 में इंडियन काउंसिल ऐक्ट तथा 1909, 1919 और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट के तीन अलग-अलग संस्करणों में भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। आजादी से संबंधित 1947 के कानून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट नाम दिया गया। संविधान सभा में भी हमारे राष्ट्र के नामकरण को लेकर चर्चा हुई थी। 18 सितंबर, 1948 को संविधान के अनुच्छेद-1 से जुड़ा संशोधन हरि विष्णु कामत पेश कर रहे थे। देश के नामकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, 'कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम की जरूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है, लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारतभूमि नाम रखना चाहते हैं, उनका तर्क है कि यह इस धरती का सबसे पुराना नाम है।' कामत की बात पर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर खड़े हो गए थे। दक्षिण और गैर हिंदीभाषी राज्यों के सदस्यों ने भी भारत नाम पर आपत्ति जताई। उसके बाद सदन में भारत अर्थात इंडिया प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई, जो गिर गया। दूसरे कई प्रस्ताव भी गिर गए। आखिर में 'इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स' नामकरण सदन से पारित हो गया। यह अलग बात है कि समय-समय पर इंडिया की जगह भारत नाम रखने की बात हुई। वर्ष 2004 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इंडिया के बजाय देश का नाम भारत रखे जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। ऐसे ही, वर्ष 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक जनहित याचिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि देश को इंडिया के बजाय भारत न कहा जाए। बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिया के बजाय भारत कहे जाने से संबंधित जनहित याचिका खारिज कर दी थी। अगर सरकार प्रस्तावना में %वी द पीपल ऑफ इंडिया% की जगह भारत शब्द जोड़ना चाहती है, तो उसे संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से इसे पारित कराना होगा। साथ ही, देश की आधी विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। इसके बाद भी यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है।

# बहुध्रुवीय विश्व बनाने की दिशा में भारत की निर्णायक पहल

**बिक्रम उपाध्याय**

जी 20 के दिल्ली सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब कोई भी देश दुनिया का चौधरी नहीं रहा। दिल्ली डिक्लेयरेशन या दिल्ली घोषणा पत्र ने एक साथ कई मिथकों को तोड़ डाला है। ना तो अमेरिका समेत पश्चिम के देश अपनी मर्जी से कोई शब्द या वाक्य जुड़वा सकें, और ना ही चीन और रूस के एजेंडे को कोई जगह दी गई। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक वाक्य कहा कि, बाली बाली था और दिल्ली दिल्ली है, तब बहुतों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में वही किया जो वह करना चाहता था। खुद रूस के विदेश मंत्री इस बात पर अचंभित थे कि भारत ने यह कारनामा किया कैसे? लावरोव के शब्द थे- मैं भारत की भूमिका की सराहना करता हूं, और जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि जी 20 के सदस्य देश अपने व्यक्तिगत एजेंडे को ना चलाएं। दिल्ली डिक्लेयरेशन में सब कुछ संतुलित था। सभी सदस्य देशों ने शांति सुरक्षा और आपसी टकरावों को खत्म करने के उपायों पर साथ चलने पर सहमति जताई।%% यही लावरोव थे जिन्होंने दिल्ली शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कहा था कि यदि जी 20 सम्मेलन में यूक्रेन पर रूस के नजरिए को स्वीकार नहीं किया गया तो रूस घोषणा पत्र जारी नहीं करने देगा। भारत ने रूस की इस धमकी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना ही रूस के नजरिए को समझने और पश्चिम के देशों के प्रति उसकी राय पर ध्यान ही दिया। बल्कि प्रस्ताव में यह बात शामिल करा दी कि कोई भी देश किसी राजनीतिक रूप से संप्रभु देश पर कब्जे के लिए हमला नहीं करेगा और ना ही परमाणु युद्ध के किसी विकल्प पर विचार करेगा। बात साफ थी कि युद्ध का डर कई देश एक दूसरे को दिखाते रहते हैं इसलिए रूस तक ही यह बात सीमित नहीं रहनी चाहिए। भारत ने इस संबंध में बहुत ही साफ रूख रखा और सीधा तर्क दिया कि जी 20 मंच पर आर्थिक समस्याओं पर ही चर्चा हो सकती है, सुरक्षा संबंधी विषयों पर नहीं। इसलिए अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की इस पहल पर कि कम से कम बाली की तरह यहां भी यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना होनी चाहिए भारत ने इससे इंकार कर दिया। जिन देशों ने बाली का उदाहरण दिया उन्हीं के लिए एस जयशंकर ने कहा था कि बाली, बाली था, दिल्ली, दिल्ली है। पिछले साल तक जी 20 को अपाहिज बताने वाले चीन ने दिल्ली सम्मेलन के बाद कहा है कि कुछ बड़े देशों के बीच उभरे गंभीर मतभेदों और टकरावों के बावजूद जी 20 वैश्विक व्यवस्था के संचालन का सबसे उपयुक्त मंच है। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने लिखा- दिल्ली सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर अपनी वचनवद्धता दुहराई यह एक बड़ी बात थी। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली हैडोंग के हवाले से लिखा है - दिल्ली के ज्वाइंट डिक्लेरेशन से स्पष्ट होता है कि विकासशील देशों की ताकत बढ़ रही हैं और पश्चिम की आर्थिक महाशक्तियों के मुकाबले वे जी 20 को ज्यादा अच्छे तरीके से एक तटस्थ तंत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। अब जी 20 पश्चिम के कंट्रोल से बाहर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल इंडोनेशिया में हुए शिखर सम्मेलन में पश्चिम के देशों ने संयुक्त घोषणा में अपने शब्द डलवा दिए थे, लेकिन दिल्ली में वे ऐसा नही कर सके। भारत की भूमिका आने वाले दिनों में विश्व व्यवस्था में क्या होगी, इस जी 20 की बैठक के बाद इस पर भी चर्चा होने लगी है।

# डीएमके की नकारात्मक राजनीति

**उमेश चतुर्वेदी**

इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय नागपुर में हिंदू समुदाय को समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, ठीक उसी वक्त सुदूर दक्षिण में हिंदू समुदाय के कथित ब्राह्मणवाद को नष्ट करने के उद्देश्य से रामास्वामी पेरियार द्रविड़ आंदोलन की नींव रख रहे थे। दोनों संगठनों ने एक साथ तकरीबन शतकीय यात्रा पूरी कर ली है। इस पूरी यात्रा में आरएसएस विराट संगठन के रूप में उभरता है। पेरियार के समर्थक भी बढ़ चुके हैं। दोनों संगठनों में अंतर सिर्फ इतना है कि पेरियार के उत्तर भारत में समर्थक कम हैं, तो संघ की पेरियार की धरती तमिलनाडु में उपस्थिति अपेक्षानुकूल नहीं हो पायी है। दो साल बाद दोनों ही संगठनों की शतकीय पारी पूरी होगी। तमिलनाडु के युवा और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान ने इन दोनों ही संगठनों, विशेषकर पेरियार की वैचारिकी पर चर्चा का मौका दे दिया है। उदयनिधि ने हाल ही में सनातन धर्म के उन्मूलन पर केंद्रित एक सेमिनार में अपने लिखित भाषण में कोरोना वायरस और कुछ अन्य संक्रामक बीमारियों के साथ सनातन धर्म की तुलना करते हुए कहा कि इनका सिर्फ विरोध नहीं, उन्मूलन किया जाना चाहिए। कुछ यही भाषा पेरियार भी बोलते थे।

शुरू में गांधी के अनुयायी रहे पेरियार ने 1925 में तमिलनाडु के कांग्रेसी आंदोलन में ब्राह्मण वर्चस्व के विरोध में कांग्रेस छोड़ दिया, और ब्राह्मणों के विरोध में उतर गये। तमिलनाडु में देखते-देखते उनका आंदोलन फैल गया। तमिलनाडु में कांग्रेस के समानांतर उनका संगठन फैलता चला गया। पिछली सदी के 80 के दशक में एक शब्द बड़ी तेजी से फैला और राजनीति की केंद्रीय धुरी बन गया- सामाजिक न्याय। यह शब्द सही मायने में पेरियार के ही आंदोलन से उभरा। पेरियार कहने को तो छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ थे। इसके लिए उन्होंने जो शब्दावली चुनी, वह ब्राह्मणवाद का विरोध रही। सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों को बराबरी का हक दिलाने को लेकर शुरू पेरियार का आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया। उनकी भाषा इतनी आक्रामक रही कि आजादी के बाद तो

एक बार धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार माने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने पेरियार को पागलखाने तक में डालने की बात कह डाली थी। पेरियार का मानना था कि हिंदू या सनातन धर्म में जो भी कुरीतियां हैं, उसके लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार हैं। पेरियार का आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरोध में था, लेकिन देखते-देखते वह ब्राह्मण विरोध में बदल गया। पेरियार यहीं पर नहीं रुके। वे नास्तिकवाद की पैरोकारी करते-करते तमिल इलाकों के लिए अलग द्रविड़ देश की मांग पर उतर आए। उसमें आज का श्रीलंका भी था। लेकिन पेरियार के अनुयायी सीएन अन्नादुर्रै को अलग राष्ट्र की मांग पसंद नहीं आयी। उन्होंने 1949 में पेरियार के आंदोलन से नाता तोड़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम् बनायी। देखते-देखते उनका कद पेरियार से बड़ा हो गया। साठ के दशक के बाद से कुछ सालों का अपवाद छोड़ तमिलनाडु की सत्ता द्रमुक आंदोलन के हाथ रही। उदयनिधि स्टालिन उन्हीं अन्नादुर्रै के अनुयायी करुणानिधि के राजनीतिक और पारिवारिक वारिस हैं।

चूंकि तमिलनाडु में करीब 70 फीसद आबादी पिछड़े वर्ग की है और करीब 21 प्रतिशत लोग दलित हैं, लिहाजा ब्राह्मणवाद और कालांतर में ब्राह्मणविरोध की राजनीति को वहां परवान चढ़ना ही था। इसका असर यह हुआ कि राज्य के करीब तीन फीसद ब्राह्मणों के खिलाफ सूबे में माहौल जहरीला बनता गया। जिन ब्राह्मणों के खिलाफ पेरियार ने कांग्रेस छोड़ी, उस कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन पाया, और वे रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सौ साल की यात्रा में पेरियार की नास्तिक विचारधारा ने ना सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म को खारिज किया, बल्कि आर्य समाज आंदोलन, रामकृष्ण मिशन के साथ ही गांधी के सनातनी चिंतन पर भी हमला बोला। इस दौर में गांधी के साथ जिस विवेकानंद ने समानता आधारित सनातनी विचार को बढ़ावा दिया, उनको भी पेरियार ने नहीं बख्शा। अगर पेरियार की नास्तिकवादी विचारधारा और अन्नादुर्रै के द्रविड़ आंदोलन को देखें तो शुरू में वह ब्राह्मण विरोधी नजर आता है, बाद में वह उग्र हिंदी विरोधी हो जाता है। कई बार वह उत्तर भारत विरोधी भी होता नजर आता है। यह पूरा विरोध कुल मिलाकर सनातन या हिंदू दर्शन और धर्म का विरोध बनकर उभर आता है।

उदयनिधि का बयान एक तरह से पेरियार और अन्नादुर्रै के आंदोलन का समेकित रूप है। रामास्वामी पेरियार और अन्नादुर्रै के आंदोलन के बरक्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंदोलन को देखिए। संघ पर अक्सर बांटने का आरोप लगाया जाता है। विडंबना ही है कि विखंडन का यह आरोप पेरियारवादी भी लगाते हैं, जिन्होंने समाज को बांटा और एक छोटे समुदाय को सबसे ज्यादा नकारात्मक तरीके से निशाना बनाया है। वहीं समन्वय की विचारधारा पर चलता संघ तकरीबन पूरे भारत में फैल चुका है।

उसकी वैचारिकी देश की सत्ता की केंद्रीय ताकत बन चुकी है। लेकिन रामास्वामी पेरियार की वैचारिकी को देखिए, वह तमिलनाडु से बाहर अपने विस्तार के बारे में सोच भी नहीं सकती। उदयनिधि इस सीमा को जानते हैं, इसलिए वह विखंडन और नकार की राजनीति केंद्रित बयान दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या तमिलनाडु अब भी वैसा ही है, जैसा 1960 के दशक में था, जब वह हिंदी और उत्तर भारत के विरोध के नाम पर उबल पड़ता था, जब वह ब्राह्मण विरोध में आगे आता था? इस सवाल का जवाब तलाशते वक्त उस पीढ़ी के विचार को भी जानना चाहिए, जिसने हिंदी विरोधी आंदोलन में हिंदी से किनारा कर लिया। अब उस पीढ़ी को हिंदी ना सीख पाने का अफसोस है। उसे लगता है कि ऐसा करके उसने अखिल भारतीय अवसर खोया है। इसलिए वह पीढ़ी अगर चाहती है कि उसका बच्चा अखिल भारतीय सेवा में जाए तो हिंदी सिखाना नहीं भूलती।

# मोदी-शाह एक साथ कई मुद्दे उछाल कर विपक्ष को कन्फ्यूज कर देती है

**डॉ. रमेश ठाकुर**

'भारत' शब्द हमारी खाटी संस्कृति, देशी रीति-रिवाजों और पुरानी परंपराओं की आत्मा है, तभी उसे भारत माता कहके पुकारते आए हैं। गुजरा वक्त इसी शब्द से गुलजार रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों की घुसपैठ हुई, तो उन्होंने अपने मुफादित नया नाम 'इंडिया' गढ़ दिया जिसे भारतीयों को ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ा। 200 सालों तक देश उनका बंधक रहा, इस बीच ये नाम भी प्रचलित होता गया। आजादी से लेकर आजतक यानी 275 वर्षों से भारत की जगह इंडिया शब्द ही बोला और लिखा जाता रहा। समूचा संसार भी इंडिया से ही जानता-पहचानता और पुकारता है। ये सच्चाई वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया अंग्रेजों की देन है। क्योंकि इंडिया की उत्पत्ति इंडस यानी सिंधु शब्द से है जो यूनानियों द्वारा चौथी सदी ईसा पूर्व से प्रचलन में रही। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी में और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलता है।

चाहे प्राचीन भारत की बात हो, या आधुनिक समय की, दोनों के परिसंगम में हमारी परंपराओं और घरेलू संस्कृतियों में इंडिया शब्द का कोई वास्ता नहीं? पर, शायद अब भारत के माथे पर जबरन गोदा गया इंडिया नाम सदैव के लिए लुप्त होने की कगार पर है जिसकी अधिकृत शुरुआत देश की महामहिम द्वारा उस समय हुई, जब उनके कार्यालय से जी-20 कार्यक्रम को लेकर नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजे गए। निमंत्रण पत्र में उनके पद से 'इंडिया' शब्द हटा हुआ दिखा। अक्सर, भारत के राष्ट्रपति के पद के आगे 'दा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' लिखा होता था। पर, उस स्थान पर 'दा प्रेसिडेंट ऑफ भारत' शब्द दिखाई दिया। जाहिर है इसके बाद सियासी हंगामा कटता और हंगामा कटते हुए देर नहीं लगी? हिंदुस्तान के तकरीबन सभी सियासी दल केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गए हैं। सभी एक सुर में बोलने लगे कि प्रधानमंत्री संविधान से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं।

कांग्रेस नेता जयराम की टिप्पणी आई, बोले इंडिया शब्द से आपत्ति क्यों है प्रधानमंत्री को? क्या इसलिए कि जब से विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से अपने संयुक्त गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। जबकि, इससे पूर्व अपने नौ वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने अपनी करीब 150 योजनाओं के नाम इंडिया शब्द से ही रखे। चाहे खेलो इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया? विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में है। समूचा विपक्ष विशेष सत्र में इसे मजबूती से उठाएगा। लेकिन, सरकार ने सत्र आने से पहले ही ऐसा धमाका कर दिया जिससे विपक्ष में भगदड़ मच गई। उनमें अभी तक शोर सिर्फ 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर था। लेकिन एक और बड़ा बम फोड़ डाला। मोदी-शाह की जोड़ी एक बात ठीक से जानती है कि एक साथ इतने मसले उठा दो, जिससे विपक्ष कन्फ्यूज हो जाए, कि कौन-सा उठाएं, कौन-सा नहीं?

बहरहाल, 'इंडिया' को 'भारत' कर देना, ये

संवैधानिक रूप से सभी सियासी दलों के साथ मंत्रणा करने वाला मुद्दा है। हालांकि अभी भी संदेह के कुछ बादल मंडरा रहे हैं। मात्र राजनीतिक गलियारों में ही चर्चाएं हैं। स्थिति अभी भी साफ नहीं है कि वास्तव में ऐसा होगा, या संविधान से इंडिया शब्द को हमेशा के लिए हटाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए जा रहे विशेष सत्र में क्या इस मसले पर चर्चा होगी? मसौदा पेश होगा या फिर कोई बिल लाया जाएगा? वैसे, मुद्दा ज्यादा पेचीदा नहीं है कि आसानी से सुलझाया ना जाए? पर, बात वहीं आकर अटक जाती है कि क्या इस बाबत केंद्र सरकार विपक्ष को विश्वास में लेगी, या पूर्व की भांति इस बार भी सबको दरकिनार करके अपने निर्णय पर आगे बढ़ेगी। विपक्षी दल ज्यादातर इसी बात से नाखुश हैं कि सरकार किसी बड़े निर्णय में उन्हें शामिल नहीं करती, अपने मन-मुताबिक फैसले ले लेती है।

भारत-इंडिया की लड़ाई के इतर अगर बात करें, तो केंद्र में मोदी सरकार के बीते साढ़े नौ वर्षों के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला-उल्टा गया। देखा जाए तो कहीं-कहीं जरूरी भी था। मुगल, शाहजहां व अकबर जैसे तमाम पूर्व शासकों के वक्त के इतिहास को बदला गया। उनके द्वारा रखे गए नामों को हटाने का कार्य बीते कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। जैसे, पुरानी इमारतें, रेलवे स्टेशनों आदि का नया नामकरण हुआ। इसके अलावा अंग्रेजों के वक्त से चले आ रहे करीब 1500 सौ पुराने कानूनों को खत्म किया है। अंग्रेजों की बनाई संसद को भी स्वदेशी नए भवन में हस्तांतरित कर दिया गया है। इंडिया नाम पड़ने की थ्योरी से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन भारत कैसे पड़ा। इसकी मुकम्मल जानकारियों का बहुत अभाव रहा है। हालांकि, भारत शब्द के पीछे तर्क कोई एक नहीं, बल्कि बहुतेरे हैं। पर, हिंदुओं के महान पौराणिक ग्रंथ 'स्कन्द पुराण' के अध्याय संख्या-37 के मुताबिक ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र का नाम भारत था, जो बड़े बलशाली और शूरवीर थे, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भरत पड़ा। इसका उल्लेख कई जगहों पर मिल जाएगा कि भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हुआ। हिंदुस्तान शब्द की भी अपनी एक अद्भुत कहानी है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं की बहुतायत के चलते पड़ा। जबकि, ऐसा है नहीं? हिन्दू और हिन्द दोनों फारसी शब्द हैं जो इंडो-आर्यन संस्कृत सिंधु से आए हैं। आचमेनिड सम्राट डेरियस प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद ये शब्द सिंधु घाटी के लिए इस्तेमाल किया गया।

इंडिया शब्द को हटाने को लेकर सियासत में सुगबुगाहट ही नहीं, बल्कि गर्माहट भी बढ़ गई है। चर्चाएं ऐसी हैं कि हो सकता है बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान से 'इंडिया' शब्द को हटाने कोई बिल आए। प्रस्ताव की तैयारियों की हलचल दिखने भी लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत रहा है? यही रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से बाकायदा अपील की है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो। फिलहाल इस मसले को लेकर राजनीति जबरदस्त शुरू हो गई है। पर, ज्यादातर देशवासी इस पक्ष में हैं कि देश को भारत ही बोला जाए। यूरोपीय देशों की भांति अगर इस मसले को लेकर केंद्र सरकार जनमत करवाए, तो परिणाम निश्चित रूप से उनके पक्ष में होंगे। बावजूद इसके मसला भयंकर रूप से पेचीदा है, विपक्ष इतनी आसानी से इंडिया को भारत शायद ही होने दे। आगामी संसद के विशेष सत्र पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसमें क्या वास्तव में इसको लेकर केंद्र सरकार विधेयक लाएगी। अगर लाएगी तो क्या उन्हें सफलता मिलेगी। फिलहाल ये मुद्दा संसद सत्र तक गर्म रहेगा, ये तय है।

# डॉक्टर्स बोले- पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता डायबिटीज, रोगियों के लिए क्या है सलाह

डायबिटीज, गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसका साल-दर-साल वैश्विक जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि जिस गति से पिछले कुछ वर्षों में इस रोग के मामले बढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसे में आशंका है कि साल 2050 तक दुनियाभर में रोगियों की संख्या 130 करोड़ से अधिक हो सकती है। आनुवांशिकता के साथ-साथ लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण टाइप-2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सभी लोगों को इस रोग से बचाव के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

डायबिटीज की समस्या में लंबे समय से यह सवाल रहा है कि क्या इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार डायबिटीज हो जाने के बाद इसके पूरी तरह से ठीक होने की संभावना कम होती है, इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव के माध्यम से इसके लक्षणों और जटिलताओं को बस कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

**आइए जानते हैं कि डायबिटीज रोगियों के लिए विशेषज्ञों की क्या सलाह है?**

**डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं**

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ लोगों में इसे रिवर्स जरूर किया जा सकता है। आहार में बदलाव और वजन घटाने के माध्यम से ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है।

टाइप-2 डायबिटीज के लक्षणों को कंट्रोल करने का सबसे कारगर तरीका है कि आप अपने वजन को कंट्रोल रखें। कुछ किलो वजन कम करने से आपको मधुमेह का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है, यह मधुमेह के कारण होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं को भी कम करने में भी सहायक है।

**अध्ययन में क्या पता चला?**

इंग्लैंड के अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मधुमेह के रोगियों को वजन कम करने के अलावा जिस एक बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है वो है- लो कैलोरी वाले आहार का सेवन। अधिक कैलोरी वाली चीजों का सेवन करने से न सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है साथ ही इसके कारण आपका वजन भी बढ़ सकता है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने 2-5 महीनों के लिए प्रतिदिन 625-850 कैलोरी या इससे कम का सेवन किया, उनके लिए शुगर के लेवल को कंट्रोल करना अधिक आसान था। लो कैलोरी डाइट के साथ वजन को कंट्रोल करना आपके मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में काफी सहायक हो सकता है।

**डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए करें उपाय**

डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए इसको लेकर किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिदिन 10,000 कदम चलने और सप्ताह में कम से कम ढाई घंटे के मध्यम स्तरीय व्यायाम करने से न सिर्फ शुगर के स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है साथ ही यह हृदय रोगों के जोखिमों को कम करने में भी आपके लिए लाभकारी हो सकती है। शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना शरीर को स्वस्थ रखने और इसके कारण होने वाली जटिलताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

अगर आपको डायबिटीज की समस्या नहीं भी है तो भी इसे कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण इस रोग का खतरा सभी लोगों में बना हुआ है।

# लिवर को डिटॉक्स करके शुगर को कंट्रोल रखने का ये है रामबाण तरीका

**हमारे घरों** में कई ऐसी चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं, जिन्हें वर्षों से सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। घरेलू उपायों वाली ऐसी कई चीजों को मेडिकल साइंस ने भी प्रमाणित किया है।

नीम की पत्ती ऐसी ही एक अत्यंत फायदेमंद औषधि है जिसे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। तमाम अध्ययनों में भी शोधकर्ताओं ने प्रमाणित किया है कि अगर रोजाना नीम की कुछ पत्तियों का सेवन किया जाए तो इससे पूरे शरीर को कई प्रकार से लाभ हो सकता है।

हम अक्सर अपने माता-पिता और दादा-दादी को इन पत्तियों के औषधीय गुणों के बारे में बात करते हुए सुनते आ रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यह किस-किस प्रकार से हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है?

**आइए खाली पेट नीम की पत्तियों के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानते हैं।**

**त्वचा की बीमारियां होती हैं दूर**

नीम की पत्तियों में कई ऐसे औषधीय गुणों के बारे में पता चलता है जो इसे त्वचा की बीमारियों और संक्रमण को कम करने में कारगर बनाती है।

नीम में एंटी-इंफ्लामेटरी, जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो इसे त्वचा की विभिन्न समस्याओं जैसे मुंहासे से राहत दिलाने और त्वचा में इंफ्लामेशन को कम करने के लिए प्रभावी बनाते हैं।

नीम के तेल में त्वचा की लोच और चमक बनाए रखने के लिए एंटी-रिंकल और एंटी-एजिंग प्रभाव वाले आवश्यक फैटी एसिड और विटामिन भी होते हैं।

**संक्रामक रोगों से मिलती है**

**सुरक्षा**

नीम का एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपयोग रक्त शोधक के रूप में है। यह फ्री रेडिकल्स को खत्म करने, हार्मोन को नियंत्रित करने और प्रतिरक्षा को बढ़ाकर समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए भी कारगर पाया गया है। नीम का उपयोग विभिन्न हर्बल फॉर्मूलेशन में रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को हटाने और लिवर को ठीक रखने के लिए भी किया जाता रहा है। नीम बार-बार होने वाले संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती है।

**लिवर और किडनी के लिए लाभ**

नीम में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में आपके लिए लाभकारी है, इससे लिवर और किडनी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। लिवर की विषाक्तता को कम करने और इससे संबंधित संक्रमण और बीमारियों के जोखिमों से बचाव के लिए भी नीम की पत्तियों के सेवन को शोधकर्ताओं ने लाभकारी पाया है।

**नीम का सेवन करने वाले लोगों में लिवर डैमेज का खतरा भी कम हो सकता है।**

**डायबिटीज रहता है कंट्रोल**

अगर आपका अक्सर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो आप नीम के सेवन से लाभ पा सकते हैं। पशुओं पर किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि नीम की पत्ती का अर्क मधुमेह की नई दवाओं के लिए एक भी एक नया अवयव हो सकता है। नीम का अर्क उन कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मददगार पाया गया है जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। हालांकि मानवों पर इसके अध्ययन का अभाव है।

# ऐसे लक्षणों का मतलब बढ़ गया है यूरिक एसिड

**यूरिक एसिड,** हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण रसायन है जो प्यूरीन नामक पदार्थों के ब्रेक डाउन होने पर निर्मित होता है। प्यूरीन आमतौर पर शरीर में होता है और कुछ खाद्य और पेय पदार्थों में भी पाया जाता है। मैकेरल, सूखे बीन्स, मटर आदि में इसकी मात्रा अधिक होती है। वैसे तो शरीर में यूरिक एसिड की सामान्य मात्रा को नुकसानदायक नहीं माना जाता है पर इसका बढ़ना कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। हाई यूरिक एसिड की स्थिति में गठिया, उंगलियों में दर्द, किडनी स्टोन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आहार और लाइफस्टाइल को ठीक रखते हुए इसे कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक हो जाता है।

यदि आपका शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाता है या यदि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो यूरिक एसिड रक्त में जमा हो सकता है। समय के साथ यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन सकते हैं और जोड़ों में इकट्ठा होने लगते हैं।

**यूरिर एसिड बढ़ने की समस्या**

यूरिक एसिड का बढ़ना शरीर में कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक रहती है तो यह हाइपरयुरिसीमिया का कारण बन सकती है। हाइपरयुरिसीमिया के कारण यूरिक एसिड तेजी से क्रिस्टल में एक साथ चिपक जाता है। ये क्रिस्टल आपके जोड़ों में जमा होकर गठिया और गाउट की समस्या को बढ़ाने वाले हो सकते हैं साथ ही इससे किडनी में स्टोन होने और किडनी की अन्य समस्याओं का भी जोखिम हो सकता है।

**प्यूरीन वाली चीजों का कम करें सेवन**

प्यूरीन ऐसे यौगिक हैं जो कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। शरीर प्यूरीन को तोड़ता है, यह यूरिक एसिड का उत्पादन करता है।

वजन को कंट्रोल रखें

शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों से बचें

# बच्चों में कितने अलग होते हैं डेंगू के लक्षण और इसकी गंभीरता?

**दिल्ली-एनसीआर** में मच्छर जनित रोग डेंगू का खतरा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पिछले एक महीने के दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, हालांकि ज्यादातर लोग आसानी से ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, राजधानी दिल्ली में इस बार डेंगू के सबसे संक्रामक स्ट्रेन DEN-2 के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके कारण रोग के गंभीर रूप लेने का खतरा अधिक हो सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को मच्छरों के काटने से बचाव के लिए उपाय करते रहने की आवश्यकता है, डेंगू का खतरा सभी उम्र के लोगों में हो सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डेंगू वैसे तो सभी लोगों के लिए गंभीर हो सकता है पर बच्चों को इसका जोखिम अधिक देखा जाता रहा है। सभी माता-पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को मच्छरों के काटने से सुरक्षित रखें। आइए जानते हैं कि बच्चों में डेंगू के किस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं और यह किस प्रकार की जटिलताओं का कारण बन सकता है?

**डेंगू के कारण होने वाली समस्याएं**

डॉक्टर बताते हैं, डेंगू के मच्छर अक्सर दिन के समय में ज्यादा काटते हैं, इस दौरान बचाव के लिए उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। डेंगू संक्रमण की




स्थिति में तेज बुखार की समस्या के साथ सिरदर्द, शारीरिक में दर्द-थकावट और पेट में दर्द की समस्या होने का जोखिम रहता है। डेंगू के हल्के से मध्यम लक्षणों में फ्लू जैसी बीमारी होती है हालांकि इसकी गंभीर स्थिति में डेंगू शॉक सिंड्रोम और रक्तस्रावी बुखार विकसित होने का खतरा रहता है।

डेंगू के गंभीर मामलों में तेजी से ब्लड प्लेटलेट्स भी कम होने लगते हैं।

**बच्चों में डेंगू के जोखिम**

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों में डेंगू के लक्षण हल्के या गंभीर दोनों हो सकते है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें यह बीमारी पहली बार हो रही है या वह इसके पहले भी डेंगू के शिकार रहे हैं। हालांकि वयस्कों की तुलना में बच्चों में डेंगू के लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं। बच्चों में उल्टी और पेटीसिया की शिकायत होती है जबकि वयस्कों में मतली और आंखों के पीछे दर्द जैसे लक्षण अधिक आम हैं।

हालांकि डेंगू की गंभीर स्थिति में प्लेटलेट्स कम होने या रोग के गंभीर रूप लेने का खतरा दोनों में अधिक होता है।

**जानलेवा भी हो सकता है ये संक्रमण**

डॉक्टर बताते हैं, डेंगू के कुछ मामले गंभीर लक्षणों वाले और जानलेवा भी हो सकते हैं, बच्चों में इसके गंभीर मामलों को लेकर विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता होती है। ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने की स्थिति में गंभीर रोग का खतरा अधिक होता है। ये स्थिति इंटरनल ब्लीडिंग और यहां तक की मौत का भी कारण बन सकती है।

बच्चों में अगर तीन दिनों से अधिक समय तक बुखार की दिक्कत बनी हुई है और सामान्य उपचार के माध्यम से इसमें आराम नहीं मिल रहा है तो इसकी समय रहते जांच और इलाज कराया जाना जरूरी हो जाता है।

**संक्रमण से बचाव की करें उपाय**

बच्चों में डेंगू के गंभीर लक्षणों की समय रहते पहचान की जानी चाहिए। बुखार के साथ पेट में तेज दर्द, दवाओं का असर न होना और शरीर में पानी जमा होना (पेट और पैरों में सूजन) संकेत है कि बच्चे को तुरंत आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता है।

ध्यान देने वाली बात ये है कि डेंगू बुखार का अब तक कोई ज्ञात इलाज नहीं है। इसमें लक्षणों को कम करने वाले तरीकों को प्रयोग में लाया जाता है। यही कारण है कि निरंतर मच्छरों के काटने से बचाव करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और घर के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

# खांसी जुकाम के कारण गला बैठ गया

**प्रश्न : खांसी जुकाम के कारण गला बैठ गया है। बोलने में तकलीफ होती है। आयुर्वेदिक उपचार बताएं।**

**- मदन गोपाल त्रिवेदी, हैदराबाद**

उत्तर : सर्दी - जुकाम को आयुर्वेद में 'प्रतिश्याय' के नाम से जाना जाता है। प्रतिश्याय के चलते संक्रमण स्वरयंत्र तक पहुंच जाता है । और स्वरयंत्र के प्रभावित होने के कारण गला बैठ जाता है। आवाज बदल जाती है। ऐसे में नमक के पानी से गरारे करने से राहत मिलती है। खदिरादि वटी के चूसने से स्वर ठीक होने लगता है। इसमें ऊंझा लवंगादि वटी या यष्टिमधु घनवटी के चूसने से भी आराम मिलता है। ऊंझा कंठ सुधार वटी गले के बैठने की स्थिति में उपयोगी है। इसमें यष्टिमधु मिला रहने से यह कफ को भी आसानी से निकाल देता है। मुलैठी के टुकड़े या मुलैठी घन को चूसने से भी राहत मिलती है। हल्का ज्वर रहने की स्थिति में ऊंझा संशमनी वटी, कफकुठार रस और चौंसठ प्रहरी पिपर लेने से लाभ होता है।



रक्त में रक्त कणिकाओं की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी होने से रोगी का रंग पीताभ हो जाता है। इसके पूर्व रूप में हृदय में अत्यधिक स्पंदन,( पल्पिटेशन) मुख का सूखना , पसीना कम आना, और शरीर में थकावट होना आदि होते हैं ।

इसके प्रमुख लक्षणों में : पीतभासता, भोजन के पचाने की शक्ति में कमी, भोजन में अरुचि, अत्यधिक लालास्राव, थकावट, कमजोरी, शरीर की कांति का ह्रास, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, ज्वर, ठंडे पदार्थों से अरुचि, हाथ पैरों में दर्द व ऐंठन, शरीर में भारीपन, श्रम पर श्वासकष्ट आदि मिलते हैं ।मोटी भाषा में इसे ₹एनीमियार या

**स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। कृपया आयुर्वेदिक चिकित्सा बताएं।**

**- केशव शर्मा, वरंगल**

उत्तर : आपकी ये सारे लक्षण संग्रहणी से मिलते हैं। इसमें मंदाग्नि और अपच की तकलीफ रहती है। खाया हुआ अच्छी तरह से पचता नहीं है, इसी कारण कमजोरी और सुस्ती रहती है। आप सुबह शाम ऊंझा कुटजघन वटी एवं औरा ट्रायोगान टेबलेट भोजन के बाद पानी से लेवे। भोजन के बाद ही ऊंझा बिल्वासव 20 मिलीलीटर की मात्रा में 50 मिलीलीटर गुनगुने पानी में मिलाकर भोजन करने के बाद लेवें। गरिष्ठ भोजन, तले हुए पदार्थ, मैदा व बेसन के बने पदार्थ, मसालेदार व्यंजन का सेवन बंद कर दें। यह चिकित्सा कम से कम 2 मंडल तक करें। एक मंडल 40 दिन का होता है।

# चीनी की जगह खाएं ये 'फायदेमंद चीज', पाचन की समस्या से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने तक में इसके लाभ

चीनी के अधिक सेवन को स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से हानिकारक माना जाता है, इससे न सिर्फ ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने का खतरा रहता है साथ ही वजन बढ़ने, मेटाबॉलिज्म की सेहत और हृदय रोगों का भी इससे खतरा हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी लोगों को कम से कम मात्रा में चीनी का सेवन करने की सलाह देते हैं। अगर आप चीनी को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, तो यह सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपकी भी मीठा खाने की आदत रही है और लाख कोशिशों के बाद भी मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको चीनी के स्वस्थ विकल्पों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। गुड़ खाना इसमें आपके लिए सबसे लाभकारी हो सकता है। कई अध्ययनों में विशेषज्ञों ने पाया कि गुड़ न सिर्फ



आपको मीठा स्वाद देता है साथ ही इससे कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं।

**गुड़ खाने के फायदे**

अध्यनकर्ताओं ने पाया कि चीनी की जगह गुड़ खाना अच्छा विकल्प हो सकता है, इससे आप कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी पा सकते हैं। साल 2015 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, परिष्कृत सफेद चीनी की तुलना में गुड़ अधिक पौष्टिक विकल्प है। गुड़ के सेवन से शरीर के लिए प्रोटीन और पोटेशियम जैसी चीजों की भी पूर्ति की जा सकती है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अलावा डायबिटीज रोगियों के लिए भी यह अच्छा विकल्प माना जाता है।

**डायबिटीज रोगी खा सकते हैं गुड़?**

डायबिटीज में गुड़ खाना चाहिए या नहीं, यह लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, गुड़ का सेवन चीनी से बेहतर है, डायबिटीज की स्थिति में इसका कम मात्रा में सेवन किया जा सकता है। चीनी की तरह इसके दुष्प्रभाव नहीं हैं, साथ ही यह पाचन और इम्युनिटी को ठीक रखने में भी आपके लिए मददगार है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए हमेशा से बड़ी समस्या रही है। हालांकि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक (84) होता है ऐसे में इसका अधिक मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए कई प्रकार से दुष्प्रभावों वाला हो सकता है।

**बेहतर पाचन में मिलती है मदद**

गुड़ खाना आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से लाभकारी हो सकता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाचन में मदद करता है और मल त्याग को भी बढ़ावा दे सकता है। कब्ज को रोकने के लिए इसे एक अच्छे विकल्प के तौर पर भी जाना जाता है। भारतीय खाद्य परंपरा में पाचन को बढ़ावा देने के लिए सभी लोगों को भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में गुड़ खाने की सलाह दी जाती है।

**एनीमिया की रोकथाम में भी इसके लाभ**

एनीमिया गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। भारत में महिलाओं में इसका जोखिम अधिक देखा जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि गुड़ खाना आपको एनीमिया के खतरे से बचाने में मददगार हो सकता है।

गुड़ में प्रति 100 ग्राम में लगभग 11 मिलीग्राम आयरन होता है, हालांकि हमेशा ध्यान रखें बहुत अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। आयरन के साथ-साथ गुड़ खाना शरीर के लिए और भी कई प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करने में सहायक है, ऐसे में इसे सेहत के लिए बेहतर विकल्प माना जा सकता है।

# वेट लॉस में बेहद फायदेमंद हैं मशरूम की ये रेसिपीज, कुछ ही समय में दिखने लगेगा असर

कुछ लोग वेट लॉस के चक्कर में अपनी डाइट से कई चीजों को बाहर कर देते हैं। अगर आप भी वजन ना घटने से परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस एक चीज को अपनी डाइट में शामिल कर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं।आज के समय् में मोटापा लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बड़ी संख्या में लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वहीं बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए कई एड़ी-जोटी का जोर लगाते हैं। कुछ लोग डाइटिंग का सहारा लेते हैं, तो कुछ लोग घंटो जिम में पसीना बहाते हैं। लेकिन इसके बार भी रिजल्ट ना मिलने पर निराश हो जाते हैं। कुछ लोग वेट लॉस के चक्कर में अपनी डाइट से कई चीजों को बाहर कर देते हैं। अगर आप भी वजन ना घटने से परेशान हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

हम आपको इस आर्टिकल के जरिए एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर अपना वेट आसानी से घटा सकते हैं। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में मशरूम को जरूर शामिल करना चाहिए। बता दें कि मशरूम सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। मशरूम में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, विटामिन-बी, विटामिन-डी, जिंक, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वहीं इसमें कैलोरी काफी कम होती है। जिससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। आइए जानते हैं वेट लॉस के लिए मशरूम का किस तरह से सेवन करना फायदेमंद होता है।वेट ल़ॉस के लिए आपको ब्रेकफास्ट में मशरूम का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको मशरूम को छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इसमें ओट्स और दलिया मिलाकर सेवन करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ी

**नईदिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को दी गई मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ा दी। अंतरिम जमानत अब 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जैसे ही पीठ सुनवाई के लिए एकत्र हुई, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ से मामले को स्थगित करने और राहत बढ़ाने का आग्रह किया। जांच एजेंसी के बयान को स्वीकार करते हुए पीठ ने जमानत की अवधि बढ़ा दी और सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत इस साल अप्रैल में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सत्येन्द्र जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मंगलवार का चिकित्सा जमानत विस्तार, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद सत्येन्द्र जैन को दिया गया तीसरा ऐसा विस्तार है।

## गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद पर नई चार्जशीट की अनुमति दी

**पटना।** देश का रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी देने के एवज में अपने, रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर जमीन लिखवाने, यानी लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वह केंद्रीय जांच एजेंसियों पर प्रताड़ना का भले जितना आरोप लगा रहे हों, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कदम आगे बढ़ा दिया है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसे पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में नई चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय से फ्रेश चार्जशीट के लिए अनुमति की अद्यतन जानकारी दी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ नई चार्जशीट के लिए अनुमति मिल गई है और रेलवे के तीन अधिकारियों के खिलाफ भी एक हफ्ते में ऐसी अनुमति मिल जाएगी।

## टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी ने फिर किया तलब

**कोलकाता।** तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर तलब किया है। ईडी ने उनसे मंगलवार को अपने कोलकाता स्थित दफ्तर में नुसरत जहां से पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन पर शहर के न्यू टाउन में फ्लैट देने का वादा कर वरिष्ठ नागरिकों से ठगी करने का आरोप है। गरियाहाट में एक रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ फ्लैट भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। कंपनी के खिलाफ फ्लैट देने के नाम पर कई बैंक कर्मचारियों से 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि इससे पहले पांच सितंबर को भी नुसरत जहां की इसी मामले में ईडी के सामने पेशी हुई थी। ईडी की जांच वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह द्वारा हाल ही में शिकायत दर्ज कराने से संबंधित है, जिसमें एक रियल एस्टेट कंपनी पर न्यू टाउन इलाके में फ्लैट देने का वादा करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

## ममता बनजी स्पेन और दुबई की 11 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना

**कोलकाता।** पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन और दुबई की 11 दिवसीय यात्रा के लिए मंगलवार सुबह रवाना हो गईं। इस दौरान वह राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। बनर्जी ने सुबह नौ बजकर 40 मिनट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई के लिए उड़ान भरी। बनर्जी संपर्क उड़ान की अनुपलब्धता के कारण रात में दुबई में ही रहेंगी और अगले दिन स्पेन की राजधानी मैड्रिड के लिए रवाना होंगी। उन्होंने राज्य सचिववालय 'नबन्ना' में मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ''हम तीन दिन तक मैड्रिड में रहेंगे। इस दौरान हम एक वाणिज्यिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और अनिवासी बंगालियों से मिलेंगे। वहां से हम बार्सिलोना के लिए ट्रेन लेंगे, जहां हम 'बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट' (बीजीबीएस) की दो दिवसीय बैठक में भाग लेंगे।' उन्होंने कहा कि यह पांच साल में उनका पहला विदेशी दौरा होगा।

## पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह के बयान पर शिवसेना का वार

**मुंबई।** केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। उनका यह बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने पूर्व सेना प्रमुख पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वह पद पर थे, तब कोशिश करनी चाहिए थी। संजय राउत ने कहा कि हमने हमेशा सपना देखा है कि अखंड भारत हो। हम हमेशा कहते हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन जब पूर्व सेना प्रमुख पद पर थे, तो उन्हें इसे अपना बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने पूछा कि अब आप इसे कैसे ले सकते हो? उन्होंने कहा कि अगर इस दिशा में कोई प्रयास किया जाता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। राउत ने कहा कि इससे पहले मणिपुर में शांति लाना जरूरी है। चीन मणिपुर तक पहुंच गया है।

# मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ क्यों बेच रहे नफरत : भाजपा

**नई दिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को निशाना बनाने का उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा है। पार्टी ने दावा किया कि प्राचीन आस्था पर हमला कांग्रेस और उसके नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।

भगवा पार्टी ने द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन को मुख्य रूप से सनातन विचारधारा का विरोध करने के लिए बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या संविधान किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार देता है? क्या इंडिया गठबंधन के सदस्यों को संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन, कांग्रेस, सोनिया और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत क्यों बेची जा रही है। नड्डा ने आरोप लगाया, नफरत का यह मेगा मॉल केवल सत्ता के लिए है। फूट डालो और राज करो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की संस्कृति और विरासत का रोजाना अपमान किया जा रहा है, जबकि सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ नेता चुप हैं। प्रसाद ने कहा कि बिहार के मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जैसे हिंदू पवित्र ग्रंथों की बार-बार आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने भी चुप्पी साधी हुई है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की चुप्पी की स्वाकारोक्ति का संकेत है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष द्वारा एजेंडा तय किए जाने के बाद भाजपा इस मुद्दे पर लोगों के पास जाएगी। उन्होंने कहा, हम विकास के साथ-साथ विकास भी बात करेंगे। भारत सनातन का यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

### सनातन का विरोध विपक्ष का एजेंडा : भाजपा

सनातन को लेकर देश की राजनीति गर्म है। उदयनीधि के बयान के बाद के भाजपा पूरे मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। एक बार फिर से भाजपा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि इनका एजेंडा अब सामने आ रहा है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन धर्म के ऊपर घमण्डिया गठबंधन के लोग ऐसे ऐसे प्रहार कर हैं और नए नए तरीके से कर रहे हैं कि पार्टी का दृष्टिकोण बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। उन्होंने कहा कि पहला सवाल सोनिया गांधी से है। भाजपा की ओर से सोनिया गांधी जी से कई सवाल पूछे गए हैं और विस्तार से पूछा था कि रोज भारत की संस्कृति, विरासत और सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। लेकिन उस पर सोनिया गांधी जी खामोश क्यों हैं? भाजपा नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी ये सवाल पूछा गया था कि आप इस पर खामोश क्यों हैं? लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

## सनातन धर्म और राष्ट्रवाद पर ढोंगियों से प्रमाणपत्र नहीं चाहिए : कांग्रेस

**नई दिल्ली।** बीजेपी द्वारा विपक्षी गठबंधन इंडिया को लगातार सनातन विरोधी बताए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि भाजपा से हमें राष्ट्रवाद, सनातन धर्म और आजादी के आंदोलन में योगदान पर प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने ये टिप्पणी डीएमके नेता पोनमुडी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया के बाद की। उन्होंने यह भी कहा, हमें किसी से भी, खासतौर पर ढोंगियों से प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब पर उसका स्कोर निल बटे सन्नाटा है। डीएमके सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का एक बयान चर्चा में है। पोनमुडी यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध और उसे खत्म के लिए हुआ है। उन्होंने ये टिप्पणी उसी सम्मेलन में की, जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, कोरोना और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी और इसके उन्मूलन का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर भारतीय सेब उत्पादक किसानों के हितों का नुकसान करने वाला फैसला लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिदुस्तान आते हैं और अपने देश के किसानों के लिए उपहार लेकर चले जाते हैं। अमेरिका के सेब पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी जाती है। मोदी जी, अमेरिका के किसानों को उपहार दे रहे हैं और अपने देश के किसानों पर चाबुक चला रहे हैं। जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे- सेब पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। लेकिन अब खबरें हैं कि मोदी ने अमेरिका को कमिटमेंट किया है कि अमेरिका के सेब पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है, जो कभी 70% थी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता- मोदी ने ऐसा कमिटमेंट अडानी और अमेरिका से किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, मोदी जी, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अपने सेब किसानों पर चाबुक चला रहे हैं। हिमाचल में अनुमानित 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जहां की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब के बागानों से आता है।

# कांग्रेस ने गुजरात की 26 सीटों के लिए बनाई रणनीति

### प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गढ़ में कांग्रेस की बड़ी तैयारी

**नईदिल्ली।** 2024 लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि, मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन में 26 राजनीतिक दल हैं जो भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए हैं। विभिन्न राज्यों में गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के गढ़ में कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी की है। जी हां, हम बात गुजरात के कर रहे हैं। गुजरात की लोकसभा की 26 सीटों के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी और सोची-समझी रणनीति बनाई है। गुजरात की कुल 26 सीटों को कांग्रेस ने तीन भागों में बांटा है और इसकी कमान अलग-अलग व्यक्तियों को सौंपी है।

पार्टी के एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, गुजरात में 26 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारियां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के तीन सचिवों के बीच बांट दी गई हैं। एआईसीसी सचिव रामकिशन ओझा को नौ सीटों - अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, खेड़ा, आनंद, गांधीनगर, मेहसाणा, बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच, कर्नाटक से आने वाले एआईसीसी सचिव बी एम संदीप कुमार को भावनगर, अमरेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर और कच्छ का प्रभार दिया गया है। आंध्र प्रदेश से कुमार की सहयोगी उषा नायडू को शेष सीटों के लिए जिम्मेदारी दी गई है। वह पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, बारडोली, नवसारी, सूरत और वलसाड के लिए जिम्मेदार होंगी।

### सीटों का बंटवारा मुद्दा नहीं

विपक्ष के गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की घटक आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और अक्टूबर में गठबंधन की समिति इस बारे में निर्णय करेगी। 'आप' के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में 'इंडिया' गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फार्मूला तय किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, फिलहाल इस मुद्दे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सीटों का बंटवारा कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है।

### डीएमके नेता के बयान का कांग्रेस विधायक ने किया समर्थन

**पटना।** सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे विवादित बयान के बीच डीएमके के ही एक और नेता के. पोनमुडी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की उत्पत्ति ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। के. पोनमुडी के इस बयान का बिहार कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि के. पोनमुडी ने बिल्कुल सही बयान दिया है। पिछले 9 वर्षों से देश में मोदी मेड संविधान का लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा चलाए गए तमाम कुरितियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है।

खेल
प्रमुख समाचार

## महिला एशियन चैंपियन ट्राफी में 6 देश लेंगे हिस्सा

**नईदिल्ली।** भारतीय महिला हॉकी टीम महिला एशियन चैंपियन ट्राफी में अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अनुसार टूर्नामेंट की शुरुआत मलेशिया और जापान के बीच होने वाले मैच से होगी जबकि भारत का सामना पहले दिन ही थाईलैंड से होगा। यह दिन का तीसरा मैच होगा।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, चीन और भारत की टीमें भाग लेंगी। यह प्रतियोगिता पांच नवंबर तक चलेगी। भारतीय टीम अभी अच्छी फॉर्म में है। उसने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था जबकि पिछले साल स्पेन में एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप में खिताब हासिल किया था। भारत ने 2016 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी जबकि 2018 में वह उप विजेता रहा था। भारत ग्रुप चरण में अपना आखिरी मैच दो नवंबर को कोरिया के खिलाफ खेलेगा। सभी टीमों को एक ग्रुप में रखा गया है। चोटी पर रहने वाली चार टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। ग्रुप चरण में टॉप पर रहने वाली टीम चौथे नंबर की टीम से भिड़ेगी जबकि दूसरा सेमीफाइनल दूसरे और तीसरे नंबर की टीम के बीच खेला जाएगा। महिला एशियन चैंपियन ट्राफी का मौजूदा चैंपियन जापान है लेकिन इस बार उसे कोरिया और भारत से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। कोरिया ने अभी तक सर्वाधिक तीन बार यह ट्रॉफी जीती है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

## सेंसेक्स लगातार 8वें दिन चढ़कर 67,221 पर बंद

**नईदिल्ली।** वैश्विक बाजारों में मिलेजुले रुख के बीच बीएसई सेंसेक्स ने मंगलवार को लगातार आठवें दिन अपनी तेजी जारी रखी जबकि निफ्टी एक दिन पहले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 94.05 अंक या 0.14 प्रतिशत चढ़कर 67,221.13 पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह 412.02 अंक या 0.61 प्रतिशत उछलकर 67,539.10 पर पहुंच गया था। हालांकि, निफ्टी ने अपनी तेजी को गंवा दिया और उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 3.15 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 19,993.20 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 114 अंक या 0.57 प्रतिशत चढ़कर 20,110.35 के अपने नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। सेंसेक्स की कंपनियों में टीसीएस का शेयर सबसे ज्यादा 2.91 प्रतिशत चढ़ा।

## अपडेटर सर्विसेज को आईपीओ के लिए मिली सेबी की मंजूरी

**नईदिल्ली।** एंटिग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। आईपीओ में 400 करोड़ रुपये तक के नए इक्विटी शेयर और एक प्रमोटर तथा मौजूदा शेयरधारकों के 1.33 करोड़ के इक्विटी शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल होगी। अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड ने मार्च में बाजार नियामक के समक्ष मसौदा पत्र दाखिल किया था। उसे चार सितंबर को अपना अवलोकन पत्र मिला। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की भाषा में उसके अवलोकन का तात्पर्य आरंभिक शेयर बिक्री शुरू करने के लिए उसकी मंजूरी से है।

## एलन मस्क की सैटेलाइट कंपनी कर सकती है भारत में एंट्री

**नईदिल्ली।** दुनिया के सबसे अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में अपनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू कर सकती है। खबर के मुताबिक, कंपनी को जल्द ही दूरसंचार मंत्रालय से इसकी अनुमति मिल सकती है। सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक करीब एक महीने से भारत में अपनी सर्विस शुरू करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे गृह मंत्रालय से परमिशन नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है मंत्रालय सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस लाइसेंस के लिए स्टारलिंक के प्रपोजल पर विचार कर सकता है। सूत्र ने यह भी कहा कि इस लाइसेंस के पास होने की भी उम्मीद है। जीएमपीसीएस के बाद स्टारलिंक को सरकार के कई विभागों और भारत के स्पेस मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके बाद, कंपनी अपने ऑपरेशन को देशभर में शुरू कर सकती है।

## प्रधानमंत्री ने सिआम से कहा- यह ग्रीन एनर्जी का वक्त

**नईदिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाहन निर्माताओं से कॉर्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक स्थायी गतिशील इकोसिस्टम इस वक्त की मांग है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) के 63वें वार्षिक सम्मेलन में एक संदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि गतिशीलता यानी बदलाव आज के भारत में विकास का एक प्रमुख जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज समय की मांग एक मोबिलिटी इकोसिस्टम विकसित करने की है जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। पर्यावरण के प्रति जागरूक और आर्थिक रूप से संतुलित मोबिलिटी ही भविष्य है।' उन्होंने कहा, 'पावरट्रेन टेक्नोलॉजी की की एक बड़ी चेन के साथ वाहनों की शुरूआत के जरिये डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के प्रयास उल्लेखनीय हैं।

# भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर के आर्थिक और राजनीतिक मायने

**कमलेश पांडे**

वसुधैव कुटुम्बकम से लेकर पूंजीवाद तक के लिए मुफीद ग्लोबल विलेज की अवधारणा के दृष्टिगत तेजी से बदलती दुनियादारी के बीच जी 20 देशों के नई दिल्ली घोषणा पत्र के अलावा प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर की जो घोषणा हुई है, उसके वैश्विक व क्षेत्रीय आर्थिक और सामरिक मायने अहम हैं। निकट भविष्य में इनके आकार लेते ही राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मायने भी प्रभावित होने लगें तो कोई हैरत की बात नहीं होगी।

सच कहूं तो आरएसएस और भाजपा की जो नई रीति-नीति स्थापित हो रही है, उसके दृष्टिगत भी यह एक बेहद अहम फैसला है। जिससे चाहे अखंड भारत का स्वप्न हो या फिर वसुधैव कुटुम्बकम का, इस प्रस्तावित वैश्विक आर्थिक गलियारे से दोनों बखूबी सधेंगे, बशर्ते कि 2024 में मोदी श्री सरकार पुन: सत्ता हासिल कर ले। बताया गया है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर को दुनिया के आठ देश मिलकर बनाएंगे, जो भारत से इजरायल होते हुए यूरोप तक जाएगा।

मसलन, इस कॉरिडोर के निर्माण में भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। ये वो देश हैं, जो चीन के मुकाबले भारत को अपने ज्यादा करीब मानते आए हैं-लोकतांत्रिक और आर्थिक दोनों नजरिए से। इसलिए प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जी-20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली का वह ऐतिहासिक फैसला है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी।

जानकारों की राय में, इस नए गलियारे के फैसले से भू-राजनीतिक रूप से न केवल एशिया और यूरोप के देश एक दूसरे के बेहद करीब आएंगे, बल्कि अशांत मध्यपूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयत्न भी करेंगे। इस नजरिए से देखा जाए तो यह एक बेहतर, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए एक साथ काम करने के लिए संकल्प लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बेजोड़ नमूनों में से एक है। नया गलियारा भारत के प्रतिद्वंद्वी देश चीन के वन बेल्ट, वन रोड परियोजना के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय विकल्प के रूप में भी आंका जाने लगा है। इससे चीन व उसके समर्थक देशों को मिर्ची भी लगी होगी, लेकिन मोदी डिप्लोमेसी के सामने न तो किसी की चलती है और न ही कुछ चलने देने के लिए कोई कमी अपनी नीति में वो छोड़ते हैं, जो भारत के बढ़ते वैश्विक सामर्थ्य का प्रतीक बन चुके हैं। भारत से यूरोप तक प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसे दक्षिण एशिया, मध्यपूर्व और अफ्रीका के कई देशों ने अपनाया है। इसलिए अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नया प्रस्तावित आर्थिक गलियारा किस गति से लागू किया जाता है और इसके सामूहिक ध्येय की प्रतिपूर्ति में कितनी ईमानदारी बरती जाती है। भारत से मध्यपूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि इससे वैश्विक बुनियादी ढांचे, निवेश के लिए साझेदारी, आवाजाही और सतत विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इतने बड़े कदम के साथ हम भविष्य के विकास के लिए बीज बो रहे हैं। जो आपसी विश्वास मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभायेगा। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी (पीजीआईआई) के जरिए ग्लोबल साउथ देशों में बुनियादी ढांचे का अंतर भरने में हम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर यूरोप की सक्रियता का प्रतीक है। क्योंकि यूरोपीय संघ ने 2021-27 में दुनिया में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के लिए 300 मिलियन यूरो निर्धारित किये थे, जिसका समर्थन यूरोपीय संघ को, भारत, अरब व यूरोप को प्रमुख हितधारक बना देगा।

# विजय पथ पर निकला भाजपा का परिवर्तन रथ

## भाजपा सरकार के कार्यों का स्मरण कराने आया हूं: डॉ. रमन

## भ्रष्ट, निकम्मी, झूठी सरकार को उखाड़ फेंकें : अरुण साव

## भाजपा प्रदेश प्रभारी माथुर ने दिखाई रथ को हरी झंडी

**दंतेवाड़ा/रायपुर।** छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में विजय के संकल्प के साथ आज बस्तर के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की आराधना और विशाल आम सभा के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा के रथ को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से आरंभ हुई परिवर्तन यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने अपने जोशीले भाषण में कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार झूठ की सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। बस्तर को विकास की यात्रा में फिर से शामिल करना है। बस्तर की जनता कुर्सी में बैठाना जानती है तो उठाना भी जानती है। 5 साल से बस्तर का विकास ठप है बस्तर के 12 विधायक आदिवासी भाइयों बहनों को लूटने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल है। टारगेट किलिंग चल रही है। बस्तर के लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। यदि बस्तर के लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क चाहते हैं तो यह सिर्फ भाजपा दे सकती है। 15 साल तक भाजपा ने बस्तर को वह सब दिया है। जो कांग्रेस 50 साल में नहीं दे सकी। हम गांव जाते हैं तो एक ही आवाज आती है कि इसी साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे और अगले साल लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाना है तो नवंबर में कमल खिलाना है बस्तर की 12 की 12 सीट भाजपा की झोली में दें और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, झूठी सरकार से छुटकारा पाएं।

### भूपेश सरकार आदिवासियों का केवल शोषण कर रही - चंदेल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर आज परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ है। यह यात्रा विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह संकल्प मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य का विकास किया। राज्य की जनता के जीवन में खुशहाली लाई। भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ और बस्तर के आदिवासियों का केवल शोषण कर रही है। भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आने वाले समय में कमल खिलाना है और बस्तर के विकास को आगे बढ़ाना है। बस्तर की सभी 12 सीट भारतीय जनता पार्टी को सौंप कर ऐसी सरकार बनाएं जो जनता की भावनाओं के अनुरूप बस्तर और प्रदेश का विकास कर सके। हमारी सरकार ने जहां छत्तीसगढ़ को छोड़ा था, वहां से 5 साल में एक कदम भी विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ाया गया है। प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है। बस्तर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बस्तर की खुशहाली के लिए भाजपा की सरकार बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।



### परिवर्तन यात्रा का मतलब है सत्ता का परिवर्तन - सरोज

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा का मतलब है सत्ता का परिवर्तन। परिवर्तन इसलिए जरुररी है कि आज से 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी के नेता बस्तर आए और उन्होंने जनता के बीच में तरह तरह के खेल दिखाए। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनायें। उन्होंने परिवर्तन की बात की और झूठा खेल दिखाकर जनता को लुभाने का प्रयास किया था। उन्होंने हम बहनों के साथ छल किया। बहुत सारे वादे किए लेकिन कोई वादे नहीं निभाए घोषणा पत्र में 36 वादे किए गए थे। कांग्रेस की सरकार अब भरोसे का सम्मेलन करती है। भूपेश सरकार पर भरोसा तो कांग्रेस को ही नहीं है। सब जगह लिखा रहता था भूपेश है तो भरोसा है। अब जहां जहां भूपेश लिखा रहता था वहां भूपेश मिटा कर कांग्रेस लिखा जा रहा है। कांग्रेस के सम्मेलन में बड़े बुजुर्ग मल्लिकार्जुन आए थे। उनके व्यक्तित्व का यह आलम है कि जब भरोसे के सम्मेलन में बोलने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उठकर चले गए। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि भाजपा की सरकार में रेडी टू ईट योजना से जिन महिलाओं को घर चलाने के लिए पैसा मिलता था, भूपेश बघेल ने उनका रोजगार छीनकर ठेकेदार को कम दिया है। यह भरोसे की कैसी सरकार है। इस झूठी सरकार ने जो कहा किसी काम को पूरा नहीं किया। आज हम परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार की विफलता से जुड़े इन सब विषयों को लेकर भाजपा के नेता जनता के बीच जा रहे हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा तो दिल्ली तक में होती है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आदिवासियों के शोषण और भ्रष्टाचार के अलावा सरकार का कोई काम सामने नहीं आया है। 5 साल से जनता का शोषण चल रहा है। अब हद हो चुकी है। इस सरकार से छुटकारा चाहिए। यह तभी संभव है जब आने वाले चुनाव में कमल खिलाएं और भाजपा की सरकार बनाएं।

## हमने चरणपादुकाएं दीं तो हमारा मजाक उड़ाया : डॉ. रमन

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार के 5 साल में सामने आए सारे घोटालों का उल्लेख करते हुए भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया। 500 करोड़ कोयला में खा गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मोहन मरकाम ने विधानसभा में डीएमएफ घोटाले का आरोप लगाया। डॉ.रमन सिंह ने कहा कि सीधी बात करने आया हूं। आपके आशीर्वाद से डॉ. रमन तीन बार मुख्यमंत्री रहा है। यह आपका आशीर्वाद है। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास की कल्पना को साकार करने का काम किया है। बस्तर के कई मुद्दे थे। 2003 में मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले बस्तर की सबसे बड़ी समस्या थी नमक। नमक के बदले हमारे वनवासियों की कीमती वनोपजों को लूटा जाता था। नमक शोषण का औजार बन गया था। उससे मुक्ति दिलाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने निःशुल्क नमक दिया। नमक बस्तर के स्वाभिमान से जुड़ा है। आदिवासियों को कोदो, कुटकी पेज, पसिया के सहारे जीवन यापन करना पड़ता था। भूख से मौत होती थी। एक बड़ा निर्णय लिया। भाजपा की सरकार के मुखिया के नाते गरीबों को 1 रुपये किलो चावल दिया तो उससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? बस्तर अंधेरे में डूब गया था। हमने उजाला फैलाने इंतजाम किया। फिर कभी बस्तर में अंधेरा नहीं होने दिया। छत्तीसगढ़ में पलायन को रोकने के लिए गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने हमने गरीब परिवारों को 1 रुपये किलो चावल देने की योजना शुरू की। तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के प्रति कांग्रेस सरकार की संवेदना नहीं है। हमने 1280 करोड रुपए बोनस दिया है। भूपेश बघेल बोनस खा गए हैं हमने चरणपादुकाएं दीं तो हमारा मजाक उड़ाया गया था। अपने माता बहनों के पैरों की सुरक्षा के तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के लिए चरण पादुका दी। वह योजना कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। तेंदूपत्ता तोड़ने वालों का अपमान किया। किसानों को 16 प्रतिशत ब्याज पर सहकारी बैंक से कर्ज लेना पड़ता था। उसे हटाकर बिना ब्याज के कर्ज देने की शुरुआत भाजपा सरकार ने की। भाजपा सरकार की उपलब्धि का चिंतन आपको करना पड़ेगा। चमचमाती सड़क का जाल बिछाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। बस्तर में जितने भी पुल पुलिया स्कूल अस्पताल बने हैं, यह सारे के सारे निर्माण कार्य भाजपा की सरकार ने किए हैं।

## बाबू भैया की कलम से

# क्या 'एक देश-एक चुनाव' की सोच अभी ही जरूरी!

अखबार की सुर्खियों के अनुसार केन्द्र सरकार चाहती है कि 'एक देश-एक चुनाव' की सुविधा बनाई जावे ताकि आर्थिक बोझ कम हो। आचार संहिता के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं, उसमें कमी आए। लोगों को अन्य कार्य करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान हो। यह तो हुए प्रत्यक्ष लाभ, अब इसमें कई राजनैतिक चुनावी लाभ भी छुपे हुए हैं जो केंद्र शायद सार्वजनिक नहीं करना चाहती। वो यह है कि एक चुनाव में एक पार्टी को अधिक लाभ होता है। पूर्व के आंकड़ों के अनुभव कुछ यही कहते नजर आ रहे हैं। यह भी कि एक चुनाव में स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे, केन्द्रीय मुद्दे ऊपर हो जाएंगे। चुनाव खर्च भी महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। 6000 करोड़ से ज्यादा चंदा पाने वाली भाजपा कहीं सभी को पछाड़ कर आगे न आ जाए। जिनके चुनाव 2023 नवम्बर में होने हैं उन पर या तो राष्ट्रपति शासन का खतरा होगा या उनका कार्यकाल 5 साल से आगे बढ़ा दिया जाएगा। यह म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में हो सकने की संभावना बनती है। अगर कार्यकाल बढ़ाया जाता है या राष्ट्रपति शासन उस गैप में लगाया जाता है। दोनों के लिए राज्यों से आपसी सहमति के साथ संविधान की धाराओं में बड़ा संशोधन लाने की जरूरत होगी। अगर समय बढ़ाने से संविधान संशोधन हुआ तो राज्यों को काम करने का अवसर और मिल जाएगा। राष्ट्रपति शासन के लिए लाया गया तो गैर कांग्रेसी सरकारों का किया धरा माटी में मिलाने का काम विपक्ष वहां कर देगी। अगर राष्ट्रपति अगले चुनाव तक पद पर बने रहने का अस्थाई प्रावधान करते हैं तो कोई लाभ नहीं क्योंकि पावरलैस अस्थाई सरकार सिर्फ रूटिन के काम ही कर पाएगी। दिसम्बर 24 तक 12 राज्यों में चुनाव होने हैं वे सभी इसी स्थिति का सामना करेंगे। सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार में अपने पिक पर पहुंच चुके छत्तीसगढ़, राजस्थान, म.प्र. जैसे प्रमुख बड़े राज्य पर पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 'एक देश-एक चुनाव' के लिए एक समिति भी बन गई। और सबको चौंकाते हुए विशेष सत्र बुलाए जाने का एलान कर इस बहस को बल दे दिया गया। सभी दलों की अनजाने राजनैतिक हमले की सोच से धडक़ने तेज हो गई। हालांकि राजनैतिक संवैधानिक जानकार यह कहते हैं कि चुनावी राज्यों में पडने् वाले गैप के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना आसान काम नहीं। इसकी संभावना भी नहीं के बराबर बताई जा रही है। इस हालत में ये राज्य सोच में पड़ गए कि अगर यह सोच 'एक देश-एक चुनाव' को और कौन से रास्ते से साकार की जाएगी। क्या 2024 में देशभर की राज्य सरकारों का विघटन करने की तैयारी है। इसके लिए तो बहुत बड़ी सहमति व आधार की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ भी करने के लिए संविधान में बड़ा संशोधन किया जाना जरूरी होगा। हालांकि बहुमत के आधार पर भाजपा की गठबंधन वाली सरकार कुछ भी करने में सक्षम मानी जा रही है। यह इतना आसान नहीं कि राज्यों की सहमति उन्हें आसानी से मिल जाए। नवाचार करने वाली मोदी सरकार कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी कर सकती है। ऐसा मानने वाले इस सोच को भी 'तानाशाही' का नाम देते हैं। लोग मानते हैं कि प्रजातंत्र व संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह रास्ता किसी के पास नहीं दिखता कि वे रोकने करेंगे क्या? भाजपा व उनके गठबंधन के लोग मोदी के इस कदम से जरूर भीतर-भीतर अपना लाभ मानकर खुश हो रहे होंगे। लेकिन यह संशोधन अगर हो गया तो यह मान कर चलो कि मोदी की किसी भी बात या सोच का विरोध या तो बंद हो जाएगा अथवा करने की हिम्मत ही नहीं बचेगी।

यह आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि 1951 से जब से चुनाव होने शुरु हुए तब से 1961 तक 15 साल साथ में चुनाव हुए। उसके बाद विधानसभाओं के समय पूर्व अवसान अथवा बर्खास्तगी के कारण इसमें व्यवधान हो गया। तब के चुनावी दौर में कई विधानसभा सीटों पर एक आदिवासी अथवा एसटी के साथ एक सामान्य वर्ग का प्रत्याशी भी चुनाव लड़ते थे। यानि एक विधानसभा में दो विधायक भी हुआ करते थे। यह व्यवस्था सुरक्षित सीट ना होने की स्थिति में उक्त क्षेत्र की जाति बाहुल्यता के आधार पर तय की जाती थी। अंतराल में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जबकि देश में दो या तीन चार दल प्रमुख रूप से मौजूद थे। तब तक यह प्रथा चली।

अब तक ना जाने राज्यों में कितने उतार-चढ़ाव क्षेत्रीय दलों के उत्थान-पतन के दौरान आ गए। एक साथ चुनाव का तारतम्य लगभग टूट सा गया। अब तक हर दूसरे-तीसरे माह किसी ना किसी राज्य का चुनाव आ जाता है। पिछले सिर्फ लोकसभा चुनाव में 6000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ। राज्यों के चुनाव की गिनती इसमें नहीं है। अनुमान किया जा सकता है कि लाख करोड़ से ऊपर मेहनत व पसीने की जनता की कमाई राजनैतिक दांव-पेंच की भेंट चढ़ जाती है। यही पैसा विकास में खर्च होना चाहिए। यह सोचने में अच्छा तो लग रहा है लेकिन अब राजनीतिक दांव-पेंच के कारण पैदा हुई यह स्थिति सुधरेगी कैसे? अंत में यदि केन्द्र सरकार नेक नीयत से यह विचार सामने ला रही है तो इसके लिए सारी संभव चौतरफा कोशिशें होनी चाहिए। अन्यथा यह विचार ही देश में संवैधानिक उथल-पुथल मचाकर रख देगा, इसकी संभावना अधिक है। मंथन जारी है, देखे ऊंच किस करवट बैठता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

## रेलवे को बर्बाद करने की साजिश के खिलाफ जनआंदोलन:बैज

**रायपुर।** मोदी सरकार द्वारा लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किये जाने और ट्रेनों की लेटलतीफी के विरोध में तथा यात्री ट्रेनों की सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन प्रदेश के सभी जिलों में करेगी। जहां रेलवे ट्रेक नहीं है वहां पर आंदोलन प्रदर्शन कर जिलाधीश को ज्ञापन देकर विरोध किया जायेगा।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि केंद्र का रेलवे को लेकर रवैय्या जन विरोधी है। मोदी सरकार यात्री रेल और रेल सुविधाओं को बंद करने का षड़यंत्र कर रही है देश भर में यात्री गाड़ियां बंद की जा रही है, यात्री गाड़िया अचानक रद्द कर दी जाती है, यात्री गाड़ियां घंटों नहीं दो-दो दिन लेट चल रही है। रेलवे को लेकर मोदी सरकार की कार्य प्रणाली से ऐसा प्रतीत हो रहा मोदी सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सुविधा परिवहन के निजीकरण का षडयंत्र रच रही है। मोदी सरकार ने देश की सबसे विश्वसनीय नागरिक परिवहन सुविधा मानी जानी वाली रेल सुविधा को मजाक बनाकर रख दिया है। पहले से आने जाने की तैयारी का ट्रेन की टिकट आरक्षित कराए जनता के साथ धोखा मोदी सरकार कर रही है। बीते 3 साल से अधिक हो चुका है जब ट्रेनों को अचानक स्थगित कर दिया जा रहा है।

## भीड़ नहीं जुटी इसलिये शाह परिवर्तन यात्रा शुरू करने नहीं आएं : कांग्रेस

**रायपुर।** राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा को जनता ने शुरू होने के पहले ही नकार दिया। भीड़ नहीं जुटी इसलिये अमित शाह परिवर्तन यात्रा में बस्तर नहीं आये। अमित शाह के कार्यक्रम में पहले भी भीड़ नहीं जुटी थी। उनके द्वारा आरोप पत्र लांच के कार्यक्रम में दो तीन सौ लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाये। सराईपाली में भी अमित शाह की सभा में भीड़ नहीं जुटी थी तो भाजपा को उड़ीसा से लोगों को ढोकर लाना पड़ा था। जब ओम माथुर भाजपा के परिवर्तन रथ की पूजा कर रहे थे तो कोई भी भाजपा का स्थानीय नेता नहीं था। यह बताता है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा को जनता के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम में भीड़ नहीं आने के कारण नाराज अमित शाह ने ओम माथुर, रमन सिंह, अरूण साव को फटकार लगाने दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के हालात में परिवर्तन लाने 2013 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली थी जिस परिवर्तन यात्रा पर भाजपा की तत्कालीन रमन सरकार ने आपराधिक राजनैतिक षड़यंत्र कर सुरक्षा हटा कर हमला करवाया था और 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुये हमले के कारण कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं सहित 31 लोग शहीद हुये थे। भाजपा भी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की बेशर्मीपूर्वक नकल करके परिवर्तन यात्रा निकाल रही है।

## आरटीई के लंबित भुगतान के लिए निजी विद्यालय कर सकेंगे दावा

**रायपुर।** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अन्तर्गत जिन विद्यालयों के द्वारा विगत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 दोनो वर्षों का दावा नही किया गया है उनके लिये विभाग द्वारा आरटीई पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020-21 के लंबित भुगतान दावा के लिए 21 एवं 22 सितम्बर 2023 को तथा वर्ष 2021-22 के लंबित भुगतान दावा के लिए 25 एवं 26 सितम्बर 2023 तक पोर्टल को खोला जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में समस्त निजी विद्यालयों को सूचित किया गया है, ताकि वे निर्धारित तिथियों में दावा करें। संबंधित निजी विद्यालयों के दावा राशि के सत्यापन उपरांत पात्र विद्यालयों के खाते में राशि अन्तरित करने की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ प्राईवेट स्कूल एसोसियेशन के द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कंडिका-5 में उल्लेख किया गया है कि, शुल्क प्रतिपूर्ति की लगभग 250 करोड़ रूपए की राशि लंबित है, जिसका भुगतान किया जाए।प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि जिन निजी विद्यालयों का भुगतान लंबित है उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित समय पर दावा नहीं किया गया है, या उनके द्वारा नोडल अधिकारी से सत्यापन करा कर आवश्यक दस्तावेज समय पर जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

## अपनी योजना के साथ भूपेश सरकार ने रचा है कीर्तिमान: वर्मा

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार ने न केवल अपनी योजनाओ के बल्कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत सरकार के आँकड़ों के मुताबिक़ 100 दिन का काम देने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे हैं। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में जनसंख्या के अनुपात में और सर्वाधिक कार्ड बनाने और एक दिन में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ के नाम है। आवास निर्माण में गुणवत्ता और संख्या को लेकर भी छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। वन अधिकार अधिनियम के तहत हितग्राहियों को 5 लाख़ 17 हज़ार से अधिक पट्टे आवंटित कर छत्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी है। गोधन न्याय योजना की ख्याति देश दुनियां में हो रही है। नीति आयोग, केंद्रीय संसद की कृषि विभाग की स्थाई कमेटी सहित दर्जन भर राज्यों के अध्ययन दल ने प्रसंशा की है। लेकिन दलीय चटुकारिया में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता जन सरोकार के विषय पर भी केवल झूठे तथ्यों के सहारे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वायदे से ज्यादा योजनाओं को धरातल पर उतारकर जन अपेक्षाओं में खरा उतर चुकी भूपेश सरकार के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के सारे पैंतरे नाकाम रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम जनता की समृद्धि भूपेश सरकार की प्राथमिकता है। 36 में से 34 वादे साढ़े चार साल के भीतर पूरे करने वाली भूपेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी के लिए 53 योजनाएं संचालित है।



## भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी से पूरा प्रदेश त्रस्त : चंदेल

**रायपुर।** विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मंगलवार को दंतेवाड़ा से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता में की गई टिप्पणी को अनर्गल प्रलाप बताया है। श्री चंदेल ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी से पूरा प्रदेश संत्रस्त है और अब प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, और इसी डर से सहमे कांग्रेस के लोग गाहे-बगाहे रोज नया झूठ गढ़कर प्रदेश को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यात्रा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दंतेवाड़ा नहीं पहुँच पाने पर जिस तरह भीड़ नहीं जुटने का झूठ परोसने में कांग्रेस के लोग लगे हैं, वह झूठी वाहवाही बटोरकर ओछी राजनीति करती कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का घिनौना प्रदर्शन ही है। श्री चंदेल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के लिए देश और उसकी समस्याओं का समाधान व देश के विकास के मुद्दे पहली प्राथमिकता हैं और पार्टी उनकी दूसरी प्राथमिकता है। जब भी देश और पार्टी में अपनी भूमिका निभाने का अवसर आता है, भाजपा पहले देश के मुद्दे को प्राथमिकता देती है और श्री शाह ने आज भाजपा के इसी स्पष्ट दृष्टिकोण का निर्वाह किया है। दंतेवाड़ा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर उमड़ा जनसैलाब अगर कांग्रेस के लोगों को नजर नहीं आया है।



### कांग्रेस के आठ प्रश्न के जवाब में भाजपा ने दागे 16 सवाल

# सवाल का समय खत्म, अब जवाब दे सरकार: साव

ायपुर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के आठ प्रश्न के जवाब में 16 सवाल पूछे हैं। साव ने कहा कि परिवर्तन यात्रा शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के हाथ पैर फूल गए हैं। कांग्रेस की सांसें उखड़ गई हैं। जिस कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता को अपने पांच साल का हिसाब-किताब देना चाहिए। जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, वह परिवर्तन यात्रा के अवसर पर भाजपा से कुतर्क पूर्ण सवाल पूछ रही है। कांग्रेस को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है।



**भाजपा का कांग्रेस से सवाल**

1- झीरम के हत्यारे नक्सलियों को राहुल गांधी ने क्लीन चिट क्यों दी थी?,

2- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम का सबूत जेब में क्यों रखे हैं, क्या नक्सलियों से सौदा है?

3- सबूत छुपाने का अपराध क्यों किया गया और सबूत छुपाने के अपराधी को क्या दंड मिलना चाहिए?

4- बस्तर को दुनिया का सबसे बीमारू इलाका बनाने के लिए कांग्रेस माफी क्यों नहीं मांगती? ,

5- इलाज के अभाव में छत्तीसगढ़ के 39,000 बच्चों की मौत हुई%% सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ली ?

6- कांग्रेस का हाथ तेंदूपत्ता दलालों के साथ क्यों है? तेंदूपत्ता बोनस क्यों नहीं दिया?

7- भाजपा के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग का मकसद क्या है?

8- छत्तीसगढ़ में एक लाख से अधिक महिलाएं गायब हो गई हैं। चुप्पी क्यों ?

9-आदिवासी बच्चियों के दैहिक शोषण की घटनाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

10- अटल ने राज्य का गठन किया, कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ निर्माण का विरोध क्यों कर रहे थे?

11- आदिवासी शोषण की जिम्मेदार कांग्रेस आदिवासियों से माफी क्यों नहीं मांगती?

12- बस्तर महाराज प्रवीरचंद्र भंजदेव को गोलियों से भूनने वाली कांग्रेस ने माफी क्यों नहीं मांगी?

13- आदिवासी आरक्षण को निरस्त कराने वालों को कांग्रेस ने पुरस्कृत क्यों किया है?

14- बस्तर में जिला केडर की भर्तियां बंद कर आदिवासियों को रोजगार से वंचित क्यों किया गया?

15 - कांग्रेस नक्सलियों की प्रवक्ता बनकर सामने क्यों आती है?

16- बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों के मतांतरण के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है?

# टूल किट विवाद: हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, रमन सिंह और पात्रा ने लगाई थी याचिका

**बिलासपुर।** टूल किट विवाद पर हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की याचिका पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। भाजपा नेता संबित पात्रा और पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने अपने खिलाफ एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट किया था। जिसमें दावा किया गया था, कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। इसमें लिखा गया था, कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसा ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी किया था। जिस पर युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था।मामले में हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों नेताओं को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस की जांच व कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले में अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर ( छ.ग. ) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.